नई दिल्ली
मंगलवार
15 सितंबर 2026
वर्षः 13, अंकः 12
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की

सहारनपुर से मुख्यमंत्री योगी ने शुरू किया था,...पेज-08

DELHIN/2014/58158

हिन्दी केवल संवाद की भाषा नहीं, बल्कि हमारी..पेज-05

एक नजर

एयर इंडिया को आव्रजन चूक के मामले में कारण बताओ नोटिस, गृह मंत्रालय ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली,एजेंसी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ी सुरक्षा और आव्रजन (इमिग्रेशन) चूक के मामले में एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले पर चर्चा के लिए गृह मंत्रालय ने मंगलवार को संबंधित हितधारकों की बैठक बुलाई है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को दी जानकारी में बताया कि नागर विमानन मंत्रालय ने कथित आव्रजन चूक को लेकर एयर इंडिया एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस चूक के चलते तीन इतालवी यात्री दिल्ली हवाई अड्डे पर आव्रजन प्रक्रिया पूरी किए बिना कनेक्टिंग उड़ान से म्यूनिख पहुंच गए थे। सूत्रों ने कहा कि इस गंभीर मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) भी एक्शन में आ गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने मंगलवार को सभी संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) की एक अहम बैठक बुलाई है। जानकारी के मुताबिक तीन इटालियन नागरिक बिना इमिग्रेशन जांच के दिल्ली से म्यूनिख चले गए। उन्होंने चार सितंबर की सुबह लुफ्थांसा की फ्लाइट LH-763 से उड़ान भरी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस मामले में एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने एयरलाइन से सात दिन के भीतर जवाब मांगा है। ये तीनों यात्री रात करीब 12:50 बजे अमृतसर से एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या ढ्ढ-1115 से दिल्ली पहुंचे थे। करीब एक घंटे बाद, 1:45 बजे, वे लुफ्थांसा की म्यूनिख जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गए। दरअसल यात्रियों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की तय प्रक्रिया से गुजरना था। इसके बजाय वे इमिग्रेशन चेकपॉइंट तक पहुंचे बिना अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में सवार हो गए।

डीआरआई ने पाकिस्तान मूल के 362 मीट्रिक टन से अधिक छुहारे किए जब्त

नई दिल्ली। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने पाकिस्तान से आयात पर लगे प्रतिबंध को दरकिनार करने की कोशिश का भंडाफोड़ करते हुए पाकिस्तान मूल के 362 मीट्रिक टन से अधिक छुहारे (ड्राई डेट्स) जब्त किए हैं। यह कार्रवाई डीआरआई के विशेष अभियान 'ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट' के तहत की गई। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने नासिक के अंबड स्थित कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर मुंबई की एक कंपनी द्वारा आयात किए गए छुहारों से भरे 13 कंटेनरों को रोका। आयात से संबंधित दस्तावेजों में माल का मूल देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) बताया गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि माल के वास्तविक स्रोत को छिपाने के लिए सुनियोजित तरीके से ट्रांस-शिपमेंट का सहारा लिया गया था। जांच के अनुसार, ये छुहारे पहले पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से यूएई के जेबेल अली बंदरगाह भेजे गए। इसके बाद वहां माल को केवल दूसरे कंटेनरों में स्थानांतरित कर भारत भेज दिया गया। जांच में यह भी पता चला कि इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा संचालित कुछ संस्थाओं की भूमिका थी। डीआरआई ने दस्तावेजों और माल की वास्तविक उत्पत्ति के बीच अंतर को गंभीरता से लेते हुए खेप को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दो मई, 2025 से पाकिस्तान से आने वाले या पाकिस्तान मूल के सभी सामानों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आयात और पारगमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

उत्तरी सीमा पर चीन के सैनिकों की तैनाती में कमी, पाकिस्तान अब भी बड़ी सुरक्षा चुनौतीः रिपोर्ट

नई दिल्ली,एजेंसी। चीन ने पिछले वर्ष भारत की उत्तरी सीमा से लगे इलाकों में सैनिकों की संख्या में कमी की है जबकि भारतीय सेना की वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के सभी सेक्टरों में अभी भी मजबूत तैनाती है वहीं, पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद, घुसपैठ और संघर्ष विराम उल्लंघन के जरिए बड़ी सुरक्षा चुनौती बना रहा। रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में यह बात कही गयी है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी सीमा से लगते क्षेत्रों में चीन की सेना (पीएलए) की तैनाती में काफी कमी आयी है। एलएसी और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में करीब 10 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड के बराबर चीनी सैनिक तैनात हैं। चीनी सैनिकों की संख्या घटने के बावजूद भारतीय सेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष के दौरान चीन के साथ लगातार राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य बातचीत से उत्तरी सीमा पर सकारात्मक बदलाव आये और स्थिरता की स्थिति बनी। 'वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन' की 33वीं और 34वीं बैठक पिछले वर्ष मार्च और जुलाई में हुई।

सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी फिर शुरू हुई और दिसंबर 2024 तथा अगस्त 2025 में ये बैठकें हुईं। तनाव में कमी का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले वर्ष अगस्त में तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए चीन यात्रा और 25-26 अक्टूबर को पूर्वी लद्दाख में हुई 23वीं कोर कमांडर स्तर की बैठक में भी दिखा। रिपोर्ट के अनुसार, पीएलए के साथ सैन्यकर्मियों की बैठकें भी सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण माहौल में हो रही हैं। वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद से उत्तरी सीमा देश के सबसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्रों में रही है। इस दौरान दोनों तरफ सैनिकों की लगातार तैनाती और सैन्य ढांचे का बड़ा विस्तार हुआ। ताजा आकलन के मुताबिक, तत्काल सैन्य तनाव कम हुआ है, लेकिन एलएसी पर किसी भी नई चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना की तैयारी मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में

पश्चिमी मोर्चे पर स्पष्ट आंकलन में पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा चुनौती का प्रमुख कारण बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियानों में 19 आतंकवादियों को मार गिराया गया। इनमें आठ पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल थे, जो कुल संख्या का करीब 40 प्रतिशत हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह आंकड़ा जम्मू-कश्मीर में छद्म युद्ध चलाने में पाकिस्तान की भूमिका को साफ तौर पर दिखाता है। नियंत्रण रेखा पर भी पाकिस्तान की भूमिका सामने आयी है। पिछले वर्ष सेना ने जम्मू-कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे 12 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया।

पिछले वर्षों के मुकाबले घुसपैठ की कोशिशें कम हुईं, लेकिन खतरे का स्वरूप बदल रहा है। आतंकवादी गतिविधियां अब अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर बढ़ रही हैं और इनमें नशीले पदार्थों तथा हथियारों और अन्य युद्ध सामग्री की तस्करी शामिल है। वर्ष 2025 में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाएं भी काफी बढ़ी हैं। भारतीय सेना ने 163 उल्लंघन दर्ज किए, जबकि 2024 में ऐसे केवल दो मामले हुए थे। इनमें से 124 उल्लंघन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए। यह अभियान 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू किया गया था, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने पर्यटकों की हत्या की थी। पिछले वर्ष 10 और 12 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद नियंत्रण रेखा पर स्थिति में काफी स्थिरता आयी , हालांकि वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस शांति को खतरे का अंत नहीं माना जाना चाहिए और स्थिति अब भी अप्रत्याशित बनी हुई है। सेना के आकलन के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के लिए स्थानीय समर्थन जुटाने की पाकिस्तान की क्षमता में काफी कमी आयी है।

पिछले वर्ष केवल एक स्थानीय युवा आतंकवादी संगठनों में शामिल हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और वे सरकारी योजनाओं और नीतियों का बढ़ता लाभ उठा रहे हैं। इससे पाकिस्तान के स्थानीय आतंकवाद के दावे को भी कमजोर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम लोगों ने विकास का रास्ता चुना है और सरकारी तथा सेना की पहलों में बड़ी संख्या में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। सेना के अनुसार, इसका असर हिंसा में कमी, प्रदर्शनों में कमी और पत्थरबाजी की घटनाएं शून्य होने के रूप में सामने आया है। यह भी कहा गया है कि खतरा अब केवल घुसपैठ और छोटे हथियारों तक सीमित नहीं है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सेना ने पिछले वर्ष ड्रोन घुसपैठ की 863 घटनाएं दर्ज कीं। इनके जरिए नशीले पदार्थों, हथियारों और अन्य युद्ध सामग्री की तस्करी की कोशिशों का नया रूप सामने आया। सुरक्षा बलों ने इस दौरान 237 ड्रोन गिराये। पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तनाव के बावजूद सेना ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार का असर आम लोगों की गतिविधियों में भी दिखा। वर्ष 2025 में केंद्र शासित प्रदेश में 2.3 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जबकि श्री अमरनाथ यात्रा में 4.13 लाख श्रद्धालु शामिल हुए। सेना के अनुसार, यह सुरक्षा स्थिति को लेकर लोगों के बढ़ते भरोसे का संकेत है।

प्रधानमंत्री 17 सितंबर को करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत के सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल सेमीकॉन इंडिया 2026 का पांचवां संस्करण 17 से 19 सितंबर तक यहां के यशोभूमि (इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर) में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इस तीन दिवसीय आयोजन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़े वैश्विक उद्योग जगत, नीति-निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, स्टार्टअप और विद्यार्थी एक मंच पर जुटेंगे।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वैश्विक सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संगठन के संयुक्त आयोजन में होने वाले इस कार्यक्रम की थीम 'सिलिकॉन टू सिस्टम: बिल्डिंग द इकोसिस्टम' रखी गई है। इसका उद्देश्य भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा और पूरी वैल्यू चेन में देश की बढ़ती क्षमताओं को दुनिया के सामने रखना है। सेमीकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक प्रदर्शक, जिनमें करीब 300 अंतरराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं, हिस्सा लेंगी। 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल और कंपनियां यहां पहुंचेंगी। करीब 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में आयोजित प्रदर्शनी में 150 से अधिक प्रमुख वक्ता अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। आयोजन में छह देश और 12 राज्य सरकारों के पवेलियन भी होंगे। इस बार प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण 'सैंड टू सिलिकॉन टू सिस्टम वैल्यू चेन एक्सपीरियंस' होगा। इसके जरिए आगंतुकों को सेमीकंडक्टर क्षेत्र की पूरी यात्रा को एक साथ समझने का अवसर मिलेगा। इसमें सेमीकंडक्टर सामग्री और निर्माण से लेकर एडवांस्ड पैकेजिंग, चिप डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम में एक स्टार्टअप पवेलियन, इनोवेशन शोकेस, स्टार्टअप प्रतियोगिता, स्टूडेंट हैकाथॉन और वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन भी होंगे। स्टार्टअप पवेलियन में करीब 40 स्टार्टअप अपने उत्पाद और नवाचार प्रदर्शित करेंगे। वहीं वर्कफोर्स डेवलपमेंट पवेलियन के जरिए माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कौशल, प्रतिभा और रोजगार के अवसरों पर फोकस किया जाएगा। तीन दिवसीय सम्मेलन में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन की मजबूती, एडवांस्ड पैकेजिंग, सेमीकंडक्टर सामग्री और उपकरण, चिप डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इनोवेशन और टैलेंट डेवलपमेंट जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इसमें छह अंतरराष्ट्रीय कंट्री राउंडटेबल, महिला सशक्तीकरण एवं नेतृत्व पर विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में चिप उद्योग से जुड़ी कई प्रमुख वैश्विक और भारतीय कंपनियों की भागीदारी अपेक्षित है। इससे कंपनियों के बीच निवेश, तकनीकी सहयोग, साझेदारी और सप्लाई-चेन से जुड़े अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

उत्तराखंड समेत अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार

नई दिल्ली,एजेंसी। उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत देशभर के अलग-अलग हिस्सों में बारिश का असर कम होता दिखाई दे रहा है लेकिन कहीं-कहीं पर अगले 6-7 दिनों के दौरान भारी बारिश के आसार हैं। इनमें उत्तराखंड सहित अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। इस दौरान वर्षा वाले क्षेत्रों में तूफानी हवाओं का रूख भी सामान्य से कुछ अधिक ही रहेगा। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को हल्की बारिश का अनुमान है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार दिल्ली में मंगलवार सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32-34 डिग्री सेल्सियस और 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बुधवार और गुरुवार को भी यही स्थिति बनी रह सकती है। दोनों दिन के न्यूनतम तापमान में लगभग एक से दो डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव बना रहेगा। आईएमडी ने राजधानी में आज मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई थी लेकिन आज उमस भरी गर्मी महसूस की गई। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उससे सटे उत्तरी गुजरात के ऊपर कम दबाव बना हुआ है। वहीं, 19 सितंबर को पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए हालात अनुकूल हो रहे हैं। उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों के हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी क्षेत्रों में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम क्षेत्रों में कोंकण और गोवा, दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलग-अलग क्षेत्रों में अगले 6-7 दिनों के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है।

भाजपा ने ब्रिक्स डिनर के शाकाहारी मेन्यू पर कांग्रेस की आलोचना को शर्मनाक बताया

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित रात्रिभोज के शाकाहारी मेन्यू को लेकर कांग्रेस की आलोचना को शर्मनाक और हास्यास्पद बताया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की उपलब्धियों के बजाय विपक्ष का पूरा ध्यान खाने के मेन्यू पर है।

डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि के बावजूद कांग्रेस ने अपनी टिप्पणी को केवल डिनर के मेन्यू तक सीमित रखा। यह न केवल हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी शादी में नाराज़ फूफा हों। इतने महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच के कूटनीतिक, रणनीतिक या आर्थिक पहलुओं पर टिप्पणी करने के बजाय उन्होंने भोजन पर टिप्पणी करना चुना।

भारतीय जहाज 'मैसूर' ने मलेशिया के समुद्री अभ्यास 'समुद्र लक्ष्मण' में हिस्सा लिया

दोनों नौसेनाओं के बीच अनुभव साझा करने और आपसी समझ को बढ़ावा मिला

नई दिल्ली,एजेंसी। ऑपरेशनल तैनाती के हिस्से के तौर पर भारतीय जहाज 'मैसूर' ने मलेशिया के लुमुट में रॉयल मलेशियन नेवी के साथ एक्सरसाइज 'समुद्र लक्ष्मण' के चौथे संस्करण में हिस्सा लिया।

इस अभ्यास ने भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियन नेवी को कई तरह की प्रोफेशनल और ऑपरेशनल गतिविधियों में शामिल होने का मौका दिया। बंदरगाह चरण में दोनों नौसेनाओं के बीच प्रोफेशनल लेन-देन और बातचीत हुई, जिससे अनुभव साझा करने और आपसी समझ को बढ़ावा मिला। नौसेना के मुताबिक यह जुड़ाव समुद्र में ऑपरेशनल फेज तक आगे बढ़ा, जिसके दौरान आईएनएस मैसूर ने रॉयल मलेशियन नेवी के जहाजों केडी लेकिर और केडी गगाह समुद्रा के साथ समुद्री अभ्यास किया। हिस्सा लेने वाले जहाजों ने मिलकर समुद्री बदलाव किए, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने, ऑपरेशनल तालमेल को बेहतर बनाने और एक साथ असरदार तरीके से काम करने की उनकी क्षमता को मजबूत करने का मौका मिला। इस अभ्यास का पूरा होना भारत और मलेशिया के बीच नेवल सहयोग की बढ़ती गहराई और मैच्योरिटी को दिखाता है। यह दोनों समुद्री सेनाओं के बीच बेहतर ऑपरेशनल समझ बनाने में लगातार प्रोफेशनल जुड़ाव और प्रैक्टिकल सहयोग की अहमियत को भी दिखाता है। नौसैन्य अभ्यास 'समुद्र लक्ष्मण' भारत-मलेशिया की बढ़ती समुद्री पार्टनरशिप में एक और अहम जुड़ाव है। एक जुलाई को हुई 12वीं भारत-मलेशिया सब कमेटी मीटिंग समेत हाल की द्विपक्षीय मुलाकातों से बनी तेजी को आगे बढ़ाते हुए इस अभ्यास ने दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग की नींव को और मजबूत किया है। आईएनएस मैसूर भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में 9 सितंबर को मलेशिया के लुमुट पहुंचा था। आईएनएस मैसूर के चालक दल का रॉयल मलेशियन नौसेना के कर्मियों और मलेशिया में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने अत्यंत उत्साह के साथ स्वागत किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर मदद के लिए 1033 हेल्पलाइन को अत्याधुनिक बनाया जाएगा

नई दिल्ली,एजेंसी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को बेहतर और तेज सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1033 हेल्पलाइन को नई तकनीक से लैस करने जा रहा है। उन्नत प्रणाली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और स्मार्ट आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि नई व्यवस्था के तहत हेल्पलाइन कॉल करने वाले की लोकेशन की पहचान कर सकेगी, विभिन्न भारतीय भाषाओं में बातचीत समझ सकेगी और जरूरत के अनुसार तेजी से सहायता उपलब्ध कराएगी। हालांकि

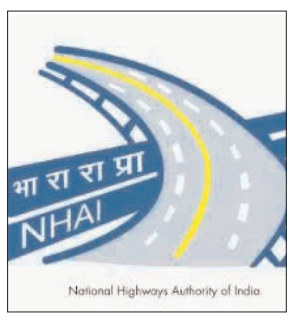

आपातकालीन स्थितियों में मानव ऑपरेटर की भूमिका पहले की तरह बनी रहेगी।

मंत्रालय के अनुसार 1033 हेल्पलाइन वर्ष 2018 से संचालित है और चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है। इसके माध्यम से चिकित्सकीय आपात स्थिति, वाहन खराब होने, एम्बुलेंस, क्रेन और पेट्रोलिंग वाहन की सहायता, टोल प्लाजा और फास्टैग संबंधी शिकायतों समेत राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है। वर्तमान में यह हेल्पलाइन 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को कवर करती है और रोजाना लगभग 15 हजार कॉल प्राप्त करती है। नई प्रणाली में सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। इसके अलावा कॉलर की लोकेशन की स्वतः पहचान, विभिन्न भारतीय भाषाओं में एआई आधारित सहायता, जरूरत के अनुसार एम्बुलेंस या अन्य संसाधनों की त्वरित तैनाती, यात्रियों को समय पर अलर्ट और आपातकालीन सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

संगमनगरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी घोषणा

प्रदेश के सक्रिय वकीलों को मिलेगी 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज की सुविधा

प्रयागराज,एजेंसी। योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को संगमनगरी में अधिवक्ता समाज को देश के प्रबुद्ध वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि अब अधिवक्ताओं को सालाना पांच लाख रुपये तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। हाई कोर्ट और जिला अदालतों में सक्रिय प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी कार्यक्रम में उन्होंने प्रदेश के उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में सक्रिय सभी अधिवक्ताओं को सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा बीमा देने की घोषणा की। साथ ही 10 हजार से अधिक अधिवक्ताओं के चैंबर में फर्नीचर और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने में शासन की ओर से सहयोग का भरोसा दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य विधि अधिकारियों को भी सुविधाएं दी जा रही हैं। प्रदेश के 400 राज्य विधि अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे और उनकी फीस में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने तथा अधिवक्ता की मृत्यु पर परिजनों को आर्थिक सहायता की पात्रता आयु 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता समाज देश के प्रबुद्ध वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वाधीनता आंदोलन से लेकर संविधान निर्माण और लोकतंत्र को मजबूत करने तक अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रयागराज की धरती भी ऐसे अनेक अधिवक्ताओं की गवाह रही है, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे अधिवक्ताओं ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि बार और बेंच न्याय के रथ के दो महत्वपूर्ण पहिए हैं। न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दोनों के बीच सम्मान, संवाद, समन्वय और सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की बैठकों में अधिवक्ताओं से जुड़े विषयों को भी प्राथमिकता दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में न्यायिक और पुलिस ढांचा बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था। कई जनपदों में जिला अदालतें अस्थायी और किराए के भवनों में चलती थीं। अब न्यायिक आधारभूत ढांचे में बड़ा बदलाव हुआ है।

'सेवा संकल्प अभियान' 17 सितंबर से, दिल्ली सरकार 13,820 करोड़ की परियोजनाओं का करेगी उद्घाटन और शिलान्यास

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक दिल्ली में एक माह का 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली सरकार के सभी विभाग जनसेवा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अभियान के दौरान दिल्ली में लगभग 13,820 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित 'सेवा संकल्प अभियान' की पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने निरंतर जनसेवा को अपना ध्येय बनाया है। उनकी कार्यशैली और सेवा के प्रति समर्पण सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर एक विशेष मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। दिल्ली सरकार के शिविर में एक ही दिन में 2,500 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित करेगा। इन शिविरों के माध्यम से लगभग 25,000 वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रम

विभाग दिल्ली में काम करने वाले श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा। अभियान के दौरान श्रमिकों का पंजीकरण कराया जाएगा और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था की जाएगी। श्रमिकों को सरकारी सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए उनका पंजीकरण महत्वपूर्ण है। इस अभियान के माध्यम से श्रमिकों तक आवश्यक सेवाएं पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अंगदान को जनसेवा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए कहा कि दिल्ली में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए एक आधिकारिक मंच स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन तैयार किया गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा संचालित व्यवस्था के अनुरूप बनाया गया है। सेवा संकल्प अभियान के दौरान इस मंच का शुभारंभ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरी विकास विभाग और दिल्ली नगर निगम के सहयोग से दिल्ली के प्रत्येक वार्ड, विधानसभा क्षेत्र और विभिन्न स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यमुना की सफाई से जुड़ी लगभग 8,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सेवा संकल्प अभियान के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पर्यावरण विभाग द्वारा 'स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली' के लक्ष्य के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पेड़-पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सेवा संकल्प अभियान के दौरान इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक वार्ड में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 'मेरे सपनों का भारत' विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें चित्रकला, भाषण और रील बनाने की प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। दिल्ली के लगभग 5,000 स्कूलों के 5 लाख विद्यार्थियों को इन प्रतियोगिताओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर की शाम 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत दिल्ली के लाभार्थी अपने-अपने घरों में दीप जलाकर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देंगे। उन्होंने बताया कि 'नमो सेवा की अनकही कहानियां' कार्यक्रम के अंतर्गत उन लाभार्थियों की वास्तविक जीवन की कहानियां सामने लाई जाएंगी, जिनके जीवन में सरकारी योजनाओं और सेवाओं से सकारात्मक परिवर्तन आया है। दिल्ली सरकार लाभार्थियों के बीच जाकर उनकी कहानियों का संकलन करेगी। इन कहानियों को वीडियो और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 10,897 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहां लगभग 21,350 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं। सेवा संकल्प अभियान के दौरान इन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 'सेवा सेतु अभियान' के अंतर्गत केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में तीन-तीन दिन के विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 'सेवा के रंग, राष्ट्र के संग' कार्यक्रम के अंतर्गत रंगोली और मंडला कला के माध्यम से विशेष आयोजन किए जाएंगे। इसके साथ-साथ देशभर में 'इनोवेशन चैलेंज' के लिए पांच केंद्र बनाए जाएंगे। प्रत्येक राज्य इसमें भाग लेगा। दिल्ली को भी इस कार्यक्रम के लिए एक केंद्र दिया गया है। दिल्ली में आसपास के राज्यों के युवाओं को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा।

मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने निगमायुक्त को लिखा पत्र

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली में मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने सोमवार को निगमायुक्त को पत्र लिखकर आवश्यक एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की। सत्या शर्मा ने कहा कि सितंबर माह में रुक-रुक कर हो रही बारिश के दौरान खाली पड़े बर्तनों, गमलों, बाल्टियों तथा अन्य स्थानों पर पानी जमा होने की संभावना बढ़ जाती है, जो मच्छरों के प्रजनन का कारण बन सकता है। इसलिए ऐसे संभावित मच्छर प्रजनन स्थलों की नियमित जांच एवं रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

सत्या शर्मा ने निगमायुक्त से कहा कि जनहित एवं नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निगम के सभी संबंधित अधिकारियों को मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सख्त एवं समयबद्ध निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से यह निर्देश दिए जाए कि सभी 12 जोनों में मच्छर प्रजनन स्थलों की नियमित जांच कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित हो। जलभराव वाले क्षेत्रों, संवेदनशील स्थानों एवं हॉटस्पॉट क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग तथा एंटी-लार्वा गतिविधियों को तेज किया जाए। स्थायी समिति अध्यक्ष ने कहा कि खाली प्लॉटों, निर्माणाधीन स्थलों, पार्कों, नालियों, स्कूलों, अस्पतालों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि कहीं भी पानी जमा होकर मच्छरों के प्रजनन का कारण न बने। उन्होंने कहा की क्षेत्रीय अधिकारियों को डेंगू एवं मलेरिया की स्थिति की नियमित समीक्षा करने तथा आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाए। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद उत्पन्न होने वाले जलभराव एवं पानी के ठहराव को तत्काल दूर करने के लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। शर्मा ने सभी वार्डों में जनप्रतिनिधियों एवं आरडब्ल्यूए के सहयोग से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने घरों एवं आसपास पानी जमा न होने देने तथा मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक किया जाना आवश्यक है। उन्होंने निगमायुक्त से कहा कि सभी जोनों से फॉगिंग, एंटी-लार्वा गतिविधियों एवं मच्छर प्रजनन स्थलों की जांच सहित की गई कार्रवाई की दैनिक रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए। स्थायी समिति अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली में मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम को प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।

दिल्ली में 500 आधुनिक सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक के लिए ईएफसी ने स्वीकृत किए 266.26 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में पहले चरण में 500 सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक बनाने का निर्णय लिया है। इनका निर्माण दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। पहले चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद शेष 500 सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक दूसरे चरण में बनाए जाएंगे। इस योजना के लिए सरकार की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने 266.26 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। यह जानकारी एक विज्ञप्ति के जरिए दी गई। विज्ञप्ति के मुताबिक, दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) की इस परियोजना में भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं को विकसित करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राजधानी के प्रमुख पर्यटन स्थलों, विरासत क्षेत्रों, बाजारों, प्रमुख मार्गों और पर्यटक आवागमन वाले क्षेत्रों में आधुनिक सार्वजनिक सुविधाओं का विकास दिल्ली को पर्यटकों के लिए अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बनाने में मदद करेगा। इन सार्वजनिक शौचालय ब्लॉकों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों के साथ दिव्यांगजनों सहित सभी लोगों के सुगम उपयोग के लिए रैंप की व्यवस्था होगी। प्रत्येक शौचालय ब्लॉक में केयरटेकर रूम और चौकीदार के लिए भी स्थान होगा। नागरिकों और पर्यटकों की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक दुकान का प्रावधान किया गया है, जहां स्नैक्स, पेय पदार्थ और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध होंगी।

राज्यसभा सचिवालय के तत्वावधान में हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ

नई दिल्ली। हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्यसभा सचिवालय के तत्वावधान में आयोजित हिंदी पखवाड़े का सोमवार को शुभारंभ हुआ। 28 सितंबर तक चलने वाले हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ हिंदी निबंध एवं सामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता, हिंदी अनुवाद एवं सामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता के आयोजन के साथ हुआ। इन प्रतियोगिताओं में सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा हिंदी के प्रति अपनी रुचि और अनुराग का परिचय दिया।

पखवाड़े के आगामी कार्यक्रमों के अंतर्गत कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता, सुलेख एवं शुद्ध लेखन प्रतियोगिता, हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा हिंदी काव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इनके माध्यम से प्रतिभागियों को हिंदी भाषा के विभिन्न आयामों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रति अपने जुड़ाव को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर संयुक्त सचिव (संपादन एवं अनुवाद) महेन्द्र

सिंह ने सचिवालय के कार्यालयी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में हो रही बढ़ोतरी की सराहना करते हुए कहा कि हिंदी पखवाड़ा केवल प्रतियोगिताओं के आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कार्यालयी कार्यों में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर हिंदी के प्रति अपने लगाव तथा राजभाषा के प्रति अपने सम्मान को अभिव्यक्त करें। हिंदी पखवाड़े का समापन पुरस्कार वितरण समारोह तथा राज्य सभा सचिवालय की वार्षिक गृह पत्रिका 'नूतन प्रतिबिंब' के 21वें अंक के लोकार्पण के साथ किया जाएगा।

दिल्ली दंगा: भजनपुरा पेट्रोल पंप हिंसा मामले में पांच लोग दोषी करार

नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान भजनपुरा के पेट्रोल पंप पर हुई हिंसा के मामले में पांच लोगों को दोषी करार दिया है। हालांकि, कोर्ट ने इन आरोपितों को पेट्रोल पंप पर आगजनी के आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने आरिफ, मोहम्मद खालिद, अब्दुल सत्तार, तनवीर अली और हुनैन को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 152, 186 और 353 के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने इन आरोपितों के खिलाफ आरोप ये साबित किया है कि वे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ हमला करने वाली भीड़ का हिस्सा थे। हमला करने के बाद पुलिसकर्मी किसी तरह पेट्रोल पंप की दीवार फांदकर भागे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 24 फरवरी, 2020 को एक सूचना मिली कि भजनपुरा थाना क्षेत्र के तहत यमुना विहार सर्विस रोड पर दिल्ली डीजल्स नामक पेट्रोल पंप पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि सौ से डेढ़ सौ की संख्या में लोग एकत्र हैं। ये सभी चांद बाग इलाके से रोड पार कर आए थे और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस मामले के ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों के बयान दर्ज काए थे, जिनमें कोर्ट ने आठ लोगों के बयानों पर भरोसा किया, जिनमें पांच पुलिसकर्मियों और बाकी पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के बयान थे। इन सभी के बयान एक-दूसरे के विरोधाभासी नहीं थे।

एमसीडी ने दिल्ली में प्रवर्तन अभियान तेज किया, 40 स्थानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, 8 संपत्तियां सील

शबाना बेगम, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने शहर के सभी 12 जोनों में खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण तथा दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) और भवन उप-नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपने प्रवर्तन अभियान को तेज कर दिया है। आज चलाए गए गहन प्रवर्तन अभियान के तहत एमसीडी के सभी 12 जोनों में 40 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इसके अलावा, 8 संपत्तियों को सील किया गया और लागू भवन मानदंडों एवं नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 14 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। एमसीडी ने कल भी प्रवर्तन कार्रवाई की थी, जिसके दौरान दिल्ली के मास्टर प्लान और भवन उप-नियमों के उल्लंघन के चलते 11 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया तथा 4 अन्य संपत्तियों को सील किया गया।

प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई वाले क्षेत्र

आज चलाए गए प्रवर्तन अभियान के दौरान करोल बाग जोन के टी.सी. कैंप, ब्लॉक-टी, पांडव नगर; ईस्ट पटेल नगर; रेगरपुरा, करोल बाग; माता रमेश्वरी, नेहरू नगर; तथा नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। ईस्ट जोन में ईस्ट विनोद नगर, मयूर विहार फेज-II, रघुबरपुरा और गांधी नगर के धरमपुरा सहित

विभिन्न क्षेत्रों में प्रवर्तन कार्रवाई की गई। नॉर्थ जोन में मलका गंज में ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई।

दिल्ली में पीजी भवनों का व्यापक सर्वेक्षण

एमसीडी अपनी निरंतर प्रवर्तन एवं निरीक्षण पहल के तहत दिल्लीभर में पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासीय भवनों का व्यापक फील्ड सर्वेक्षण भी कर रही है। इसका उद्देश्य एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना तथा आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तय करना है। अब तक किए गए सर्वेक्षण के तहत दिल्ली में लगभग 2,453 ऐसे भवनों की पहचान की गई है, जहां पीजी सुविधाएं संचालित हो रही हैं। एमसीडी लागू भवन मानदंडों और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण एवं निरीक्षण की यह प्रक्रिया लगातार जारी रखे हुए है।

डूसू चुनाव : अभाविप ने एनएसयूआई पर आंतरिक कलह और भ्रम फैलाने का लगाया आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अभाविप ने अपने चुनावी अभियान को गति देते हुए मुख्य प्रतिद्वंद्वी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) पर तीखा हमला बोला है। अभाविप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन राष्ट्रीय स्तर से लेकर छात्र राजनीति तक धरातल पर विफल साबित हुआ है और अब अपनी अंदरूनी कलह छिपाने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है। अभाविप ने दावा किया कि खुद को संविधान का रक्षक बताने वाले संगठन (एनएसयूआई) के लोगों द्वारा झंडे जलाने और अनुशासनहीनता की घटनाएं सामने आई हैं, जो उनके दोहरे चरित्र को उजागर करती हैं। संभावित हार को देखते हुए एनएसयूआई वास्तविक छात्र मुद्दों से ध्यान भटकाने के हथकंडे अपना रही है। अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा, 'जो संगठन अपने ही कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने में असमर्थ है, वह दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थियों की समस्याओं और उनकी आकांक्षाओं को कैसे संभालेगा? एनएसयूआई को विद्यार्थियों के बीच जाकर उनके मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन वह अपनी अंदरूनी कलह से ध्यान हटाने के लिए सोशल मीडिया पर भ्रम और प्रचार का सहारा ले रही है। इसके विपरीत अभाविप लगातार विद्यार्थियों के बीच जाकर उनकी बात सुन रही है और छात्रहित के मुद्दों को लेकर जमीन पर काम कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब सब कुछ देख और समझ रहे हैं। इस बार विद्यार्थियों का स्पष्ट समर्थन अभाविप के साथ है और 7-3-3-3 के साथ विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल निर्णायक विजय की ओर बढ़ रहा है। उनके अनुसार संगठन के प्रत्याशी और कार्यकर्ता विभिन्न कॉलेजों में जाकर सीधे छात्रों से संवाद कर रहे हैं और परिसर से जुड़ी मूलभूत समस्याओं व अकादमिक मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने की मेगा रक्तदान शिविर की तैयारियों की समीक्षा

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों के विभागाध्यक्षों और दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों के एमडी/एमएस के साथ एक अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के अवसर पर आयोजित होने वाले मेगा रक्तदान शिविर की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन दिल्ली सरकार के दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन (डीएसएचएम) के द्वारा 17 सितंबर को त्यागराज स्टेडियम में किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि रक्तदान सेवा के सबसे महान कार्यों में से एक है। इस मेगा रक्तदान शिविर के माध्यम से हम दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, अस्पतालों और नागरिकों की सामूहिक शक्ति को एक मानवीय उद्देश्य के लिए एकजुट करना चाहते हैं। इस बैठक में स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने वाले सभी नागरिकों के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। विभागों से कहा गया है कि वे नागरिकों को रक्तदान अभियान में शामिल होने के लिए स्वैच्छिक रूप से प्रेरित और जागरूक करें और उनकी भागीदारी को सुगम बनाएं।

इस कैंप में दिल्ली सरकार के 11 अस्पतालों के ब्लड बैंक अपना-अपना सहयोग देंगे, ये सभी अस्पताल जरूरी मेडिकल टीमें, उपकरण, कोल्ड-चेन सुविधाएं और कैंप में एकत्रित किए गए ब्लड यूनिट्स की सुरक्षित आवाजाही की समुचित व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। इस बैठक में दिल्ली पुलिस, होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस, एमसीडी, एनडीएमसी, डीटीसी, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा, दिल्ली फायर सर्विस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, राजस्व विभाग, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और अन्य संबंधित विभागों/एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ भाग लेने वाले सरकारी अस्पतालों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि भी शामिल हुए। पंकज कुमार सिंह ने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग, रक्त संग्रह, मेडिकल सहायता, सुरक्षा, एंबुलेंस सेवाएं, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और अन्य जरूरी सुविधाओं के संबंध में सुचारु व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि सभी नागरिक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से रक्तदान शिविर में भाग ले सकें।

महापौर ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र के वार्ड नंबर 51 एवं 53 का किया निरीक्षण

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत सोमवार को उत्तर पश्चिम क्षेत्र के वार्ड नंबर 51 एवं 53 का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। महापौर ने गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स पर स्थापित किए जा रहे कॉम्पेक्टरो के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। महापौर प्रवेश वाही ने बाहरी रिंग रोड पर स्थित काली माता मंदिर के पास लगे कूड़े के ढेर को देखकर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के समय ये हाल है तो आम दिनों में यहां कैसी सफाई व्यवस्था रहती होगी। महापौर ने संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने एवं कन्सेशनियर पर भारी जुर्माना लगाने के आदेश दिए। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि मंदिर में भंडारा आयोजित करने के पश्चात सफाई का विशेष ध्यान रखे या फिर दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को सफाई के संबंध में निवेदन करें। महापौर ने कहा कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वार्ड स्तर पर कूड़ा प्रबंधन को मजबूत करने, समयबद्ध तरीके से कचरे का निस्तारण सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता

बनाए रखने के लिए नगर निगम के अधिकारियों को निरंतर जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। प्रवेश वाही ने उत्तर पश्चिम दिल्ली के वार्ड नंबर-51 में स्थित सफेदा वाला पार्क के निकट स्थित निर्माणाधीन कॉम्पेक्टर का निरीक्षण किया एवं अधिकारियों को इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने ई और एफ ब्लॉक प्रशांत विहार का निरीक्षण किया और वहां चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से सड़क पर स्थित अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

महापौर ने रोहिणी सेक्टर-3 में स्थित निर्माणाधीन कॉम्पेक्टर का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे भी जल्द से जल्द चालू करने के निर्देश दिए। वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम की गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स पर कॉम्पेक्टर मशीन स्थापित करने की योजना है ताकि कूड़े का निस्तारण सही तरीके से किया जा सके। महापौर ने कहा की कूड़ा मुक्त एवं स्वच्छ दिल्ली बनाने की इस मुहिम में नागरिकों के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वो घर से निकलने वाले कूड़े को स्त्रोत पर ही पृथक करके उसका निस्तारण करें। निरीक्षण में दिल्ली नगर निगम की निर्माण समिति के उपाध्यक्ष एवं वार्ड नंबर-53 के पार्षद धर्मवीर शर्मा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के उपायुक्त अंशुल सिरोही सहित दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

एक नजर

अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई और आवारा पशुओं के प्रबंधन के दिए निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। उन्होंने सोमवार को लोक निवास में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) कमिश्नर संजीव खिरवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजधानी में चल रहे कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल ने दिल्ली में समय पर कूड़ा उठाना, सड़कों की सफाई, जल-जमाव की समस्या से निपटना, आवारा पशुओं का प्रबंधन और अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश दिए है। उन्होंने सड़कों के बार-बार टूटने और आने-जाने वालों को होने वाली परेशानी को रोकने के लिए, सड़क खोदने वाली और सड़क की देखरेख करने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उपराज्यपाल ने संबंधित विभागों को जमीनी स्तर पर काम करने और जवाबदेही तय सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

स्वतंत्र भारद्वाज की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला कर घायल करने के आरोपित स्वतंत्र भारद्वाज की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ने कल यानि 15 सितंबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से पेश वकील उमेश शर्मा ने कहा कि उन्हें राजनीतिक वजहों से फंसाया गया है। शर्मा ने कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज को एससी-एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उसके खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई।कोर्ट ने 7 सितंबर को स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने भारद्वाज को 6 सितंबर को 7 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। उसके पहले वो एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। स्वतंत्र भारद्वाज को यूपी के बुलंदशहर से 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी तब हुई थी, जब उसने एक पॉडकास्ट में इस बात को स्वीकार किया था कि उसने एक प्रदर्शनकारी छात्रा के पिता के सिर पर हमला किया। इस पॉडकास्ट के बाद काकरोच जनता पार्टी और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब स्वतंत्र भारद्वाज ने खुद ही पॉडकास्ट पर आरोप कबूल किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस प्रदर्शन के बाद स्वतंत्र भारद्वाज को यूपी के बुलंदशहर में गिरफ्तार किया गया था। स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ पॉक्सो कानून और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान काकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग साली वर्दी में लाठी और डंडे लेकर आए थे और प्रदर्शनकारियों पर हमलों को अंजाम दिया था। इस प्रदर्शन के दौरान की स्वतंत्र भारद्वाज की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई।

दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए तीन महीने से भटक रहा युवक

नोएडा,एजेंसी। दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए युवक तीन महीने से जिला अस्पताल का चक्कर काट रहा है। पहले दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बनाने का कारण यूनिक डिसिबलिटी आई (यूडीआईडी) पोर्टल में तकनीकी खराबी बताई गई। अब आवेदक के पता से संबंधित खामियां बताई गई है। सोमवार को भी प्रवीण आर्य दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने आए थे, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बना। लिहाजा उन्होंने सीएमएस से इसकी शिकायत की है। शिकायती पत्र में लिखा गया है कि 14 जून को दिव्यांग प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण कराया था। इसके बाद 3 जुलाई को उनका मेडिकल परीक्षण भी पूरा हो गया।

मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अभी तक प्रमाणपत्र और यूडीआईडी कार्ड जारी नहीं किया गया है। पहले पोर्टल पर तकनीकी दिक्कत होने की बात कही जा रही थी। अब आवेदक का पता को लेकर दिक्कत बताई गई है। परिजनों का आरोप है कि कई बार संबंधित टीम से संपर्क करने पर उन्हें यूडीआईडी वेबसाइट में तकनीकी समस्या होने की जानकारी दी गई। समस्या की जांच के लिए कई बार संपर्क किया गया, लेकिन समाधान नहीं निकला। दिव्यांग प्रमाण पत्र व्यवस्था के प्रभारी डिप्टी सीएमओ डॉ. टीकम सिंह का कहना है कि इस मामले की जानकारी नहीं है। अगर दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदक को परेशान किया जा रहा है तो कार्रवाई की जाएगी? प्रवीण आर्य की बहन निशा आर्य ने बताया कि जब वह इस मामले की शिकायत लेकर जाती तो सीएमओ के छुट्टी पर होने की बात कही जाती। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित हेल्पलाइन सेवा से भी कोई ठोस मदद नहीं मिली। जो व्यक्ति पहले से ही शारीरिक परेशानी से गुजर रहा है, उसे कागजी कार्रवाई और विभागीय चक्करों में उलझाना दुखद है। प्रवीण आर्य ने बताया कि शिकायत पत्र के बाद उनको विभाग के कॉल आया है कि उत्तराखंड जाकर ही काम होगा। उन्होंने कहा कि अगल ऐसा था तो पहले देखकर बताना चाहिए था तीन महीने का इंतजार नहीं करना होता।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय परिसर जनता को किया समर्पित

नई दिल्ली,एजेंसी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को शालीमार बाग के सिंगलपुर गांव के लेबर चौक पर नवनिर्मित सार्वजनिक शौचालय परिसर (जन सुविधा परिसर) जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा, जिला अध्यक्ष अजय खटाना, निगम पार्षद अमित नागपाल, अनीता जैन मौजूद रही। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस सार्वजनिक शौचालय में दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा गया है और उनकी सुविधा के लिए केयरटेकर की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्वच्छ, सुगम और आधुनिक सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आधुनिक सार्वजनिक शौचालय जनता को समर्पित किया और इस 1,000 आधुनिक सार्वजनिक शौचालय बनाने के लक्ष्य में से आज पहला जन सुविधा परिसर सफलतापूर्वक पूरा कर जनता को समर्पित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में साफ-सुथरे आधुनिक की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली पर्यटन को सड़कों और बाजारों में 1,000 शौचालय परिसर बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इसमें पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए 3 अलग-अलग यूनिट्स हैं, साथ ही महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की भी व्यवस्था है। 24 घंटे केयरटेकर, हर 20 परिसरों पर एक सुपरवाइजर और आधुनिक सफाई मशीनों के साथ इसका रख-रखाव सीधे सरकार करेगी। दिल्ली वासियों और आने वाले पर्यटकों के लिए यह सुविधा पूरी तरह नि:शुल्क रहेगी।

मुख्यमंत्री ने मुनक नहर के छठ घाट निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को मुनक नहर पर प्रेमबाड़ी पुल के पास चल रहे सफाई, सौंदर्यीकरण, प्रकाश व्यवस्था और भव्य छठ घाट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ तय समयसीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व से पहले मुनक नहर स्वच्छ, सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुरूप तैयार हो।

घर-घर कूड़ा उठाने वाले वाहन नहीं आने से परेशान निवासी

ट्रांस हिंडन। घर-घर से कूड़ा उठाने वाले वाहन नियमित नहीं पहुंचने के कारण वसुंधरा, वैशाली, शालीमार गार्डन समेत ट्रांस हिंडन के कई इलाकों में लोग परेशान हैं। कई स्थानों पर लोग मजबूरी में गलियों और सड़कों के किनारे कूड़ा डाल रहे हैं। इससे जगह-जगह गंदगी के ढेर लगने के साथ दुर्गंध की समस्या भी बढ़ रही है। जिससे लोगों को इलाके में रहना भी दूभर हो गया है। वसुंधरा के महाराजपुर, कड़कड़ मॉडल गांव में कई स्थानों पर लोगों के घरों के आगे कूड़ा जमा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद समय से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। निवासी मनीष सक्सेना ने बताया कि इलाके में गलियां संकरी होने के कारण कूड़ा वाहन घर-घर कूड़ा लेने के लिए नहीं आते। उन्होंने आरोप लगाया है कि कई बार गलियों के कोने तक कूड़ा वाहन लाने की मांग की है। लेकिन यहां तक भी नहीं लाया जाता। इस कारण आसपास के लोग गलियों के कोने पर और खाली स्थानों पर गंदगी फैला देते है। वहीं राजेंद्र नगर स्थित एसपीएस-2 के आरडब्लूए सचिव एमएस बिष्ट ने बताया कि सफाई कराए जाने के कुछ समय बाद ही लोग दोबारा उसी स्थान पर कूड़ा डाल देते हैं। उनका कहना है कि केवल सफाई कराना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। कूड़ा दोबारा न डाला जाए, इसके लिए निगरानी और प्रभावी व्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कूड़ा फेंकने पर रोक लगाने और नियमित निगरानी कराने की मांग की है। वहीं नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार का कहना है कि सभी इलाकों में नियमानुसार घर-घर कूड़ा वाले वाहनों को भेजा जा रहा है।

'राक्षस था मेरा पोता...गिरफ्तारी का अफसोस नहीं', गाजियाबाद में नशेड़ी पोते की हत्या के बाद 79 वर्षीय दादा का कबूलनामा

गाजियाबाद,एजेंसी। नंदग्राम के नूर नगर में शनिवार रात हुए 32 वर्षीय आशु उर्फ अश्वनी हत्याकांड का पुलिस ने महज 48 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला सच सामने आया है कि आशु की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके 79 वर्षीय दादा और चाचा ने मिलकर की थी। दोनों आशु की शराब पीने, मारपीट करने और चोरी की आदतों से बेहद परेशान थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपित दादा ने कहा, 'राक्षस था मेरा पोता। गिरफ्तारी का मुझे कोई अफसोस नहीं। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी दादा भीम सिंह ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी रची। आरोपित दादा ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात करीब 11:30 बजे बिजली न होने के कारण अंधेरा था। इसी दौरान तीन अज्ञात लोग नशे में धुत आशु को चारपाई पर लिटाकर भाग गए। रविवार सुबह जब वे आशु को चाय देने छत पर गए, तब उन्हें उसके मृत होने का पता चला।

पुलिस ने जब क्षेत्र की बिजली व्यवस्था की पड़ताल की, तो पाया कि घटना के समय पूरे इलाके में बिजली आ रही थी। केवल आशु के घर की बिजली बिल न भरने के कारण पहले से कटी हुई थी। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की, तो बुजुर्ग दादा टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामले में पुलिस ने आरोपी दादा भीम सिंह (79) और चाचा राकेश (48) को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया है। पोते की हत्या के आरोपी 79 वर्षीय भीम सिंह के चेहरे पर शिकन तक नजर नहीं आई। सोमवार को मीडियाकर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका पोता 'राक्षस' बन चुका था और उसने पूरे परिवार का जीना दुश्वार कर रखा था। आशु कोई कामकाज नहीं करता था और दिनभर शराब के नशे में घर का सामान बेच देता था या परिजनों के साथ मारपीट कर रुपये छीन लेता था। पूछताछ के दौरान भीम सिंह ने बताया कि आशु की शराब की लत और मांगों को पूरा करते-करते वे भारी कर्ज में डूब गए थे। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपना मकान 9 लाख रुपये में बेचा था। इस राशि में से 6 लाख रुपये लोन के चुकता किए गए और 1.5 लाख रुपये आशु द्वारा शराब के लिए गए कर्ज को चुकाने में खर्च हुए। इसके बावजूद आशु के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया और वह लगातार मारपीट करता रहा।

किसानों की मांगे पूरी नहीं होने तक धरना रहेगा जारी : राकेश टिकैत

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

नोएडा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जनपद गौतम बुद्ध नगर के किसानों ने नोएडा विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के दफ्तरों पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। नोएडा में किसानों के धरने में किसान नेता राकेश टिकैत ने भी भाग लिया। वह सोमवार को नोएडा पहुंचे इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में किसान भी थे जो कि अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा हुए। राकेश टिकैत नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर पर आयोजित महापंचायत में पहुंचे। इस दौरान टिकैत ने जिले की तीनों अथॉरिटी (नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी) पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने किसानों से मांगें पूरी होने तक धरने पर डटे रहने का आह्वान किया।

जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसान 10 प्रतिशत आवासीय प्लॉट, आबादी से जुड़े मामलों का निपटारा और नए कानून के अनुसार 20 फीसदी भूखंड लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा किसान चाहते हैं कि 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो। इस धरना प्रदर्शन में अलग-अलग किसान संगठन शामिल हैं। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 'तीनों अथॉरिटी से बातचीत होगी। जब तक कोई समाधान नहीं होगा और ठोस निर्णय नहीं होगा जब तक हम यहां पर रहेंगे। अगर अभी भी कोई समाधान नहीं निकलता है तो किसान दिल्ली भी कूच कर सकते हैं। हमारी मुख्य मांग यह है कि 64.7 प्रतिशत मुआवजे, जो प्लॉट दिए जाने हैं वे अलॉट किए जाएं और जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा उनका रेट बढ़ाया जाए।

'हम एक-दूसरे से अलग नहीं रह सकतीं, पति नहीं सहेली का साथ चाहिए'; प्यार में जिद पर अड़ीं महिलाएं

साहिबाबाद। खोड़ा थाना क्षेत्र की कॉलोनी में नोएडा की फैक्ट्री से लापता हुईं दो महिलाएं साथ रहती मिलीं। दोनों के परिजन जब मकान पर पहुंचे तो महिलाओं ने साथ जाने से इनकार कर दिया और एक साथ रहने की जिद पर अड़ गईं। दोनों एक-दूसरे के साथ जीवन गुजारने की बात कहती रहीं। वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया लेकिन दोनों नहीं मानीं। पुलिस तहरीर मिलने पर कार्रवाई की बात कह रही है। युवक ने बताया कि चार साल पहले उसकी शादी हुई थी। इसके बाद दोनों ग्रेटर नोएडा में रहकर एक कंपनी नौकरी करने लगे। कंपनी में कई अन्य महिला-पुरूष कामगार काम करते थे। 12 अगस्त को उनकी पत्नी लापता हो गई।

उन्होंने कंपनी के पता किया तो एक अन्य युवती भी लापता हुई थी। उन्होंने पत्नी को खोजने का प्रयास किया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद उन्होंने ईकोटेक थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। पत्नी को खोजने के दौरान उनकी मुलाकात कंपनी से लापता दूसरी युवती के भाई से हुई। इसके बाद दोनों मिलकर उन्हें खोजने लगे। उन्होंने दोनों युवतियों के सोशल मीडिया के अकाउंट चेक किए। जिनसे उनके खोड़ा में होने की जानकारी मिली।

रविवार को युवती का पति और भाई खोड़ा स्थित मकान पर पहुंचे, जहां दोनों युवतियां परिजनों को मिलीं। दोनों ने बताया कि वह यहां किराये पर रहती हैं। दोनों एक-दूसरे से प्यार करती हैं। वह एक-दूसरे से अलग नहीं रह सकतीं। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन दोनों ने परिजनों के साथ जाने से साफ मना कर दिया। इसके बाद पुलिस दोनों को थाने लेकर पहुंची। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि किसी पक्ष की ओर से लिखित तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर आने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

बिल्डर ने प्रॉपर्टी विवाद में जहरीला पदार्थ खाया

ग्रेटर नोएडा,एजेंसी। ग्रेनो वेस्ट की पाम ओलंपिया सोसाइटी में रहने वाले बिल्डर ने प्रॉपर्टी विवाद में रविवार देर रात जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालत गंभीर होने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर है। बिसरख कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक नीरज चौहान ने खुद को और परिवार को प्रताड़ना से बचाने के लिए मुख्यमंत्री, पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने कुछ लोगों पर दबाव बनाकर परेशान करने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने जहरीला पदार्थ खाया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि नीरज चौहान, निशांत दुबे और आशीष श्रीवास्तव ने मिलकर सूरजपुर थाना क्षेत्र के इटा गांव में एक प्रोजेक्ट के लिए छह एकड़ जमीन खरीदी थी। जमीन में नीरज चौहान और आशीष श्रीवास्तव की 25-25 प्रतिशत, जबकि निशांत दुबे की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

वन विभाग की टीम ने ला रेजिडेंशिया सोसाइटी से सात उल्लू पकड़े

ग्रेटर नोएडा,एजेंसी। वन विभाग की टीम ने सोमवार को ग्रेनो वेस्ट स्थित ला रेजिडेंशिया सोसाइटी में अभियान चलाकर सात उल्लुओं को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। इनमें दो उल्लू बड़े और पांच बच्चे हैं। सभी को सूरजपुर स्थित बर्ड सेंचुरी में सुरक्षित छोड़ने की तैयारी है। सोसाइटी में रहने वाले सुमिल जलोटा ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से रात के समय उल्लू के हमलों में कई लोग घायल हो गए थे। उल्लू अचानक ऊपर से आकर लोगों के सिर पर चोंच मारकर उड़ जाते थे। इन घटनाओं के बाद वन विभाग की टीम ने शनिवार को सोसाइटी का निरीक्षण किया था। टीम ने उल्लुओं के संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाने के साथ ही निगरानी और रेस्क्यू के लिए वन्यजीव संरक्षण से जुड़े एनजीओ की मदद लेने का निर्णय लिया था। इसके बाद सोसाइटी में मौजूद एनजीओ के लोगों ने दिन-रात उन उल्लुओं पर नजर रखी। वे कहां रहते हैं, उसका पता लगाकर विभाग को उसकी जानकारी दी। इसके बाद सोमवार शाम को वन विभाग की टीम दोबारा सोसाइटी पहुंची और बेहद सावधानी के साथ अलग-अलग स्थानों पर अभियान चलाया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने सात उल्लुओं को पकड़ लिया। रेस्क्यू किए गए उल्लुओं में दो वयस्क और पांच बच्चे हैं। वन विभाग की टीम उन्हें सूरजपुर स्थित बर्ड सेंचुरी ले जाएगी, जहां उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। बाद में उनके अनुकूल प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा जाएगा? लोगों ने राहत की सांस ली। उल्लुओं हमलों से सोसाइटी के लोगों में डर का माहौल था। रात के समय घर से बाहर निकलने में भी लोग सतर्कता बरत रहे थे। सात उल्लुओं के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम ने अभी कुछ दिनों तक सावधानी बरतने की अपील की। विशेष रूप से अंधेरे स्थानों पर जाने से बचने, पर्याप्त रोशनी रखने और रात में बाहर निकलते समय सिर को टोपी या कपड़े से ढकने की सलाह दी।

छात्रा आत्महत्या मामले में मानवाधिकार आयोग ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

फरीदाबाद। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने फरीदाबाद के डबुआ-गाजीपुर रोड स्थित नवोदय विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 11वीं की 16 वर्षीय छात्रा की दुखद मृत्यु के मामले में संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों से विस्तृत तथ्यात्मक एवं कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। छात्रा ने एक सितंबर, 2026 को विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल की छत से कथित रूप से छलांग लगा दी थी। अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा तथा दोनों सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया को मिलाकर बनी पूर्ण पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया कि समाचार रिपोर्टों में लगाए गए आरोपों को इस स्तर पर स्थापित तथ्य नहीं माना जा रहा है और किसी भी व्यक्ति के दोषी अथवा निर्दोष होने के संबंध में पूर्व धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। हालांकि, आरोपों की गंभीर प्रकृति बच्चों की सुरक्षा, गरिमा, मानसिक स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक संस्थानों में उनके मानव अधिकारों से संबंधित गंभीर प्रश्न उठाती है। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, छात्रा को घटना से पहले एक अध्यापक द्वारा कथित रूप से दंडित किया गया था तथा उसे कई घंटों तक धूप में खड़ा किए जाने का आरोप लगाया गया है।

विद्यालय प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया है। छात्रा के पिता की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित एफआईआर दर्ज किए जाने तथा पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य तथ्यों की जांच किए जाने की भी रिपोर्ट है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीडन् का कोई स्थान नहीं है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में बच्चों को शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीडन् से संरक्षण प्रदान किया गया है। विशेष रूप से आरटीई अधिनियम की धारा 17 स्पष्ट रूप से किसी भी बालक को शारीरिक दंड अथवा मानसिक उत्पीडन् दिए जाने पर रोक लगाती है।

अपहरण और छेड़छाड़ मामले में दोषी को छह वर्ष की कैद

ग्रेटर नोएडा,एजेंसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष कुमार चौरसिया की अदालत ने अपहरण और छेड़छाड़ के एक मामले में बिजनौर निवासी दोषी कपिल को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माने की रकम जमा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध नितिन त्यागी ने बताया कि 20 नवंबर 2015 को वादी ने सेक्टर-39 पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी बेटी एक दिन पहले 19 नवंबर की सुबह एक डिग्री कॉलेज पढ़ने के लिए घर से निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी।

परिजनों ने कॉलेज परिसर और आसपास के इलाकों में उसे काफी ढूंढा, मगर कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बाद अपहरण की आशंका के चलते थाने में तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।जांच के दौरान पुलिस ने कपिल के साथ-साथ एक नाबालिग को भी आरोपी बनाते हुए आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। हालांकि, तत्कालीन पीठासीन अधिकारी ने 13 जून 2018 को घटना के समय नाबालिग रहे आरोपी की उम्र को

देखते हुए उसका प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद यह मुकदमा केवल कपिल के खिलाफ ही अदालत में चलता रहा। अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान चार गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष बताया कि कॉलेज से घर लौटते समय सेक्टर-71 चौराहे पर पहले से जान-पहचान वाले कपिल ने उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया और देहरादून ले गया, जहां वह करीब एक सप्ताह तक रही। 26 नवंबर 2015 को जब आरोपी उसे वापस ला रहा था, तभी रास्ते में पुलिस ने दोनों को दबोच लिया था। अदालत ने पीड़िता के बयान के आधार पर पाया कि आरोपी द्वारा बलपूर्वक अपहरण किए जाने और छेड़छाड़ की घटना पूरी तरह प्रमाणित होती है। हालांकि, न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोप को लेकर बयानों में गंभीर विसंगतियां पाईं, क्योंकि पीड़िता ने स्वयं कभी दुष्कर्म का उल्लेख नहीं किया था।

सेवा संकल्प से घर-घर पहुंचेगा विकास का संदेश

कांतिलाल मांडोत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक पदों पर 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के विभिन्न राज्यों में सेवा, सुशासन और जनकल्याण को केंद्र में रखकर विशेष अभियान चलाने की तैयारी की गई है। बिहार में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, वहीं उत्तरप्रदेश में भी एक माह तक अभियान चलाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों की जानकारी गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। दोनों राज्यों में प्रस्तावित कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य राजनीतिक प्रचार से आगे बढ़कर जनता को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और सेवा कार्यों को जनभागीदारी का रूप देना बताया जा रहा है।

बिहार में अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर होगी। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से अपने घरों में दीपक जलाने की अपील की जाएगी। इसके साथ ही व्यापक स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने, आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने और वहां बच्चों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी लेने जैसे कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। विद्यार्थियों के बीच चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन कर नई पीढ़ी को देश के विकास और सामाजिक जिम्मेदारियों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी सेवा ज्योति यात्रा होगी। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन, प्रशासनिक अनुभव और देश सेवा से जुड़े कार्यों को जनता तक पहुंचाने की योजना है। जनजागरण के माध्यम से लोगों को यह बताया जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अलग-अलग वर्गों तक किस प्रकार पहुंच रहा है। ऐसे कार्यक्रमों का प्रभाव तभी व्यापक हो सकता है जब सरकारी योजनाओं की जानकारी केवल कार्यालयों और कागजी अभिलेखों तक सीमित न रहकर वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे। उत्तरप्रदेश में भी सेवा संकल्प अभियान को इसी व्यापक सोच के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी है। भाजपा की योजना गांवों और घरों तक पहुंचकर लोगों को केंद्र तथा प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान के संबंध में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक विभिन्न संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए विकास को नई दिशा दी। भाजपा के अनुसार इस अभियान के जरिए उनके सार्वजनिक जीवन और जनसेवा से जुड़े कार्यों की जानकारी समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाई जाएगी।

किसी भी सरकार की सफलता का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से होता है कि उसकी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंचा। गरीब परिवारों के लिए आवास, किसानों के लिए सहायता, महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार तथा आधारभूत ढांचे का विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब आम नागरिक इनका लाभ महसूस करे। इसलिए योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाना और पात्र लोगों को उनका लाभ दिलाना शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सेवा संकल्प अभियान को इसी दृष्टि से देखा जाए तो यह सरकार और जनता के बीच संवाद बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। गांवों में रहने वाले अनेक लोगों को कई बार सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं होती। पात्रता होने के बावजूद जानकारी के अभाव में वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। यदि कार्यकर्ता और प्रशासन मिलकर ऐसे परिवारों तक पहुंचें, उनकी समस्याएं सुनें और उन्हें संबंधित योजनाओं की जानकारी दें तो अभियान का सामाजिक महत्व और बढ़ सकता है। केवल उपलब्धियों का प्रचार करने के बजाय यदि वास्तविक समस्याओं का समाधान भी अभियान का हिस्सा बने तो जनता में इसका विश्वास और मजबूत होगा। स्वच्छता अभियान और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण जैसे कार्यक्रम इस अभियान को जमीन से जोड़ते हैं। स्वच्छता केवल किसी एक दिन चलाया जाने वाला कार्यक्रम नहीं, बल्कि निरंतर जनअभियान है। इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और मातृ-शिशु सेवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इनकी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा और स्थानीय स्तर पर सुधार से सीधे समाज के कमजोर वर्ग को लाभ मिलता है। विद्यार्थियों के लिए चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं भी बच्चों में रचनात्मकता तथा सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का माध्यम बन सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन को भाजपा विकास और सेवा की यात्रा के रूप में प्रस्तुत कर रही है। समर्थकों के अनुसार इस अवधि में गुजरात के मुख्यमंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने विकास, तकनीक, आधारभूत ढांचे और भारत की वैश्विक भूमिका को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की छवि में आए बदलाव और देश की विरासत से विकास तक की यात्रा का उल्लेख किया है। विभिन्न देशों द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मान दिए जाने को भी भाजपा उनके वैश्विक प्रभाव से जोड़कर देखती है। हालांकि किसी भी बड़े अभियान की सफलता केवल कार्यक्रमों की संख्या से नहीं, बल्कि उसके परिणामों से तय होती है। यदि सेवा संकल्प अभियान के दौरान कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनें, पात्र लाभार्थियों की पहचान करें, सरकारी योजनाओं की प्रक्रिया समझाएं और जरूरतमंदों को वास्तविक सहायता दिलाने में भूमिका निभाएं तो यह पहल अधिक प्रभावी साबित हो सकती है। जनता को केवल उपलब्धियों की जानकारी देने के साथ उसकी अपेक्षाओं और शिकायतों को सुनना भी जरूरी है।

बिहार और उत्तरप्रदेश जैसे बड़े राज्यों में ऐसे अभियान का प्रभाव व्यापक हो सकता है। दोनों राज्यों की बड़ी ग्रामीण आबादी है और यहां सरकारी योजनाओं का सीधा संबंध करोड़ों लोगों के जीवन से है। इसलिए सेवा संकल्प को यदि जनभागीदारी, पारदर्शिता और सेवा भावना से जोड़ा जाता है तो यह राजनीतिक अभियान से आगे बढ़कर सामाजिक जागरूकता का माध्यम बन सकता है। घर-घर पहुंचने वाला विकास का संदेश तभी स्थायी प्रभाव छोड़ेगा जब उसके साथ सेवा की भावना और समस्या के समाधान का भरोसा भी लोगों को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने का अवसर भाजपा के लिए निश्चित रूप से उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का अवसर है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण अवसर सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का है। बिहार का कायाकल्प अभियान हो या उत्तरप्रदेश का सेवा संकल्प अभियान, दोनों की सार्थकता इसी में है कि विकास की चर्चा केवल मंचों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव की चौपाल, गरीब की झोपड़ी, किसान का खेत, विद्यार्थी का विद्यालय और सामान्य परिवार के घर तक पहुंचे। यदि सेवा, सुशासन और जनभागीदारी इस अभियान की आधारशिला बनते हैं तो विकास का संदेश वास्तव में घर-घर पहुंच सकता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार तथा जनता के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत हो सकता है।

ब्रिक्स का सबसे बड़ा महत्व भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने में है। भारत लंबे समय से ऐसी विदेश नीति का समर्थन करता रहा है जिसमें किसी एक शक्ति-गुट पर निर्भरता के बजाय विभिन्न देशों और मंचों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संबंध बनाए जाएँ। ब्रिक्स में चीन और रूस जैसे देशों के साथ भारत की भागीदारी है, वहीं भारत अमेरिका, यूरोप, जापान और अन्य शक्तियों के साथ भी समानांतर रूप से सहयोग करता है। इस प्रकार ब्रिक्स भारत की बहु-संरेखीय विदेश नीति को व्यावहारिक आधार प्रदान करता है। ब्रिक्स का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती देना है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में आज भी अनेक निर्णय ऐसी संरचनाओं के भीतर लिए जाते हैं, जिनमें विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व उनकी आर्थिक और जनसंख्या संबंधी भूमिका के अनुरूप नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता लगातार उठाता रहा है। ब्रिक्स के माध्यम से विकासशील देश सामूहिक रूप से अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और न्यायसंगत वैश्विक शासन व्यवस्था की मांग को मजबूत कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ब्रिक्स भारत के लिए महत्वपूर्ण है। विस्तृत सदस्यता का अर्थ है बड़े बाजारों, निवेश, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग की नई संभावनाएँ।

ब्रिक्सः भारत की नई हुंकार

डॉ. सत्यवान सौरभ

ब्रिक्स आज केवल उभरती अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक समूह नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था में वैश्विक दक्षिण की आवाज को प्रभावी बनाने वाला महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चीन से बने 'ब्रिक' में 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हुआ। 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इसके पूर्ण सदस्य बने तथा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया भी पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इस विस्तार के साथ ब्रिक्स अब 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। भारत के लिए वर्ष 2026 विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भारत ने 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है और नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी प्रस्तावित है। भारत की अध्यक्षता का केंद्रीय दृष्टिकोण लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित है। यह अध्यक्षता भारत को केवल आयोजक की भूमिका नहीं देती, बल्कि समूह की प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा को प्रभावित करने का अवसर भी प्रदान करती है।

ब्रिक्स का सबसे बड़ा महत्व भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने में है। भारत लंबे समय से ऐसी विदेश नीति का समर्थन करता रहा है जिसमें किसी एक शक्ति-गुट पर निर्भरता के बजाय विभिन्न देशों और मंचों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संबंध बनाए जाएँ। ब्रिक्स में चीन और रूस जैसे देशों के साथ भारत की भागीदारी है, वहीं भारत अमेरिका, यूरोप, जापान और अन्य शक्तियों के साथ भी समानांतर रूप से सहयोग करता है। इस प्रकार ब्रिक्स भारत की बहु-संरेखीय विदेश नीति को व्यावहारिक आधार प्रदान करता है। ब्रिक्स का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती देना है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में आज भी अनेक निर्णय ऐसी संरचनाओं के भीतर लिए जाते हैं, जिनमें विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व उनकी आर्थिक और जनसंख्या संबंधी भूमिका के अनुरूप नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता लगातार उठाता रहा है। ब्रिक्स के माध्यम से विकासशील देश सामूहिक रूप से अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और न्यायसंगत वैश्विक शासन व्यवस्था की मांग को मजबूत कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी ब्रिक्स भारत के लिए महत्वपूर्ण है। विस्तृत सदस्यता का अर्थ है बड़े बाजारों, निवेश, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग की नई संभावनाएँ। भारत के लिए यह अवसर विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद, व्यापारिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ब्रिक्स के भीतर व्यापारिक बाधाओं को कम करने और भुगतान प्रणालियों को अधिक सुविधाजनक बनाने पर सहयोग भारत के आर्थिक हितों को लाभ पहुँचा सकता है। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और सीमा-पार भुगतान प्रणालियों पर सहयोग की संभावनाएँ भी इस दिशा में महत्वपूर्ण हैं। विकास वित्त के क्षेत्र में न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे और सतत विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराना है। विकासशील देशों के लिए ऐसी संस्थाएँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे पारंपरिक वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के विकल्प और पूरक दोनों के रूप में काम कर सकती हैं। भारत के लिए इसमें परिवहन, ऊर्जा, शहरी विकास, जलवायु और हरित बुनियादी ढाँचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए सहयोग की व्यापक संभावनाएँ हैं।

लेकिन ब्रिक्स के सामने चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती इसके सदस्य देशों के विविध और कई बार परस्पर विरोधी रणनीतिक हित हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद तथा व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा किसी भी गहरे राजनीतिक या सुरक्षा सहयोग को प्रभावित कर सकती है। रूस-पश्चिम संघर्ष, पश्चिम एशिया की परिस्थितियाँ और अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता जैसे वैश्विक घटनाक्रम भी ब्रिक्स के भीतर मतभेद पैदा कर सकते हैं। दूसरी चुनौती है विस्तार के बाद समन्वय की जटिलता। जब समूह छोटा था, तब साझा दृष्टिकोण बनाना अपेक्षाकृत आसान था। अब 11 पूर्ण सदस्यों और अलग-अलग स्तर के साझेदार देशों के साथ निर्णय-निर्माण अधिक जटिल हो गया है। प्रत्येक देश की आर्थिक संरचना, राजनीतिक प्राथमिकताएँ और विदेश नीति अलग हैं। इसलिए केवल संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं; साझा एजेंडा और प्रभावी संस्थागत तंत्र भी आवश्यक है। एक और गंभीर चुनौती यह है कि ब्रिक्स को कहीं पश्चिम-विरोधी गठबंधन के रूप में देखने की प्रवृत्ति न बढ़ जाए। यदि समूह को केवल अमेरिका और पश्चिमी देशों के विकल्प या प्रतिद्वंद्वी के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो उसके विकासात्मक और आर्थिक उद्देश्यों को नुकसान पहुँच सकता है। भारत के हित में यही होगा कि ब्रिक्स को किसी के विरुद्ध खड़े गुट के बजाय बहुध्रुवीय और समावेशी सहयोग मंच के रूप में विकसित किया जाए। भारत की 2026 की अध्यक्षता इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत को घोषणाओं से आगे बढ़कर व्यावहारिक परिणामों पर जोर देना चाहिए। व्यापार और निवेश, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाएँ शुरू की जा सकती हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की कार्यक्षमता और परियोजना-वित्त क्षमता को मजबूत करना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। अंततः ब्रिक्स की सफलता इस बात से तय होगी कि वह वैश्विक राजनीति में कितने प्रभावशाली बयान जारी करता है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह कितना व्यावहारिक सहयोग पैदा करता है। भारत के लिए ब्रिक्स रणनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक अवसर, वैश्विक दक्षिण की सामूहिक शक्ति और अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण विश्व व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण मंच है। इसकी विविधता चुनौती अवश्य है, लेकिन वही इसकी शक्ति भी बन सकती है। भारत को अपनी अध्यक्षता के दौरान सहमति, संवाद और विकास को केंद्र में रखकर ब्रिक्स को ऐसा मंच बनाना चाहिए, जो किसी शक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि समानता, सहयोग और संतुलित बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के पक्ष में खड़ा हो। ब्रिक्स भारत के लिए केवल कूटनीतिक मंच नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था में अपनी स्वतंत्र और प्रभावशाली भूमिका को आकार देने का अवसर है। यदि भारत अपनी अध्यक्षता को व्यावहारिक सहयोग, वैश्विक दक्षिण की एकजुटता और संतुलित कूटनीति से जोड़ने में सफल होता है, तो ब्रिक्स की नई दिशा में उसकी भूमिका निर्णायक हो सकती है।

विचार

किताबें खामोश गुरु हैं जो पीढ़ियों का भविष्य गढ़ती हैं

कांतिलाल मांडोत

लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव-2026 ने एक बार फिर यह सवाल सामने रखा है कि डिजिटल युग में पुस्तकों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। मोबाइल, सामाजिक माध्यम और इंटरनेट ने ज्ञान की दुनिया को हमारी हथेली तक पहुंचा दिया है, लेकिन इसके बावजूद पुस्तक का महत्व कम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुस्तक महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का आह्वान कर इसी आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' बच्चों को वितरित करते हुए इसे पढ़ने और जीवन में आत्मसात करने की बात कही। मुख्यमंत्री का यह संदेश केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए विचार करने योग्य है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। विद्यार्थी डिग्री और प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा देता है तो सामान्य मनुष्य जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपनी क्षमता की परीक्षा देता है। कई बार मुश्किल समय में व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। ऐसे समय में प्रेरक और जीवनोपयोगी पुस्तकें उसे मानसिक संबल देने के साथ सही दिशा दिखा सकती हैं। आज अक्सर यह कहा जाता है कि युवा पुस्तकों से दूर हो रहे हैं और सामाजिक माध्यमों पर अपना समय नष्ट कर रहे हैं। लेकिन हर युवा को एक ही दृष्टि से देखना उचित नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अच्छी और उपयोगी पुस्तकें युवाओं तक आसानी से पहुंचें। पढ़ने की सामग्री जितनी सार्थक और सहज उपलब्ध होगी, अध्ययन की रुचि भी उतनी ही बढ़ेगी।

लखनऊ पुस्तक महोत्सव की शुरुआत के पीछे भी पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने की भावना रही। युवराज मलिक ने जब लखनऊ में पुस्तक महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखा तो तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी से चर्चा कर इसे प्रोत्साहित करने की बात हुई। लखनऊ में इसके अच्छे परिणाम सामने आने के बाद गोरखपुर में भी पुस्तक महोत्सव आयोजित करने का सुझाव दिया गया। यह परंपरा बताती है कि पुस्तक मेले केवल किताबें खरीदने का अवसर नहीं, बल्कि समाज को पढ़ने की ओर मोड़ने वाले सांस्कृतिक आयोजन भी हैं। ज्ञान की आराधना पुस्तक से शुरू होकर समाज तक पहुंचती है। ज्ञान की आराधना का अर्थ केवल ग्रंथ को श्रद्धापूर्वक देखना नहीं है। ज्ञान के प्रति सच्ची श्रद्धा स्वाध्याय से प्रकट होती है। पुस्तक, कापी और लेखनी जैसे ज्ञान के साधनों का सम्मान करना, ज्ञानियों की सेवा और विनय करना, विद्वानों का बहुमान करना तथा पुस्तक लेखन, प्रकाशन, वितरण और पुस्तकालयों के लिए अपनी सामर्थ्य लगाना भी ज्ञानाराधना का ही स्वरूप है। इस दृष्टि से पुस्तकालय किसी भवन में रखी पुस्तकों का संग्रह मात्र नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक स्मृति के केंद्र हैं। एक पुस्तक में किसी लेखक का अनुभव, चिंतन और जीवन-दृष्टि सुरक्षित रहती है। जब एक पीढ़ी पुस्तक पढ़ती है तो वह केवल शब्द नहीं पढ़ती, बल्कि पिछली पीढ़ियों के अनुभवों से संवाद करती है। यही कारण है कि पुराने समय में ग्रंथों को लिखना और सुरक्षित रखना स्वयं ज्ञान की आराधना माना जाता था। माण्डवगढ़ के महामंत्री पेथडशाह का उदाहरण पुस्तक की वास्तविक शक्ति को समझाता है। पालकी में यात्रा करते समय उनके साथ अस्त्र-शस्त्र नहीं होते थे, बल्कि 'उपदेशमाला' ग्रंथ रहता था। वे यात्रा के दौरान भी उसका पारायण करते थे। उनके लिए ज्ञान सुरक्षा का ऐसा साधन था जिसकी शक्ति बाहरी साधनों से कहीं अधिक थी। महाराज कुमारपाल के समय भी ज्ञान के संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए। ताड़पत्रों पर ग्रंथ लिखे जाते थे और ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए बड़े स्तर पर संसाधन लगाए जाते थे। कुमारपाल ने शास्त्र-लेखन में करोड़ों रुपये का सदुपयोग किया तथा अनेक ज्ञान भंडार बनवाए। यह उदाहरण बताता है कि धन का सबसे श्रेष्ठ उपयोग वह है जिससे आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान की संपदा प्राप्त हो। वस्तुपाल और तेजपाल ने ज्ञान के भंडार खड़े किए थे। मंत्री वस्तुपाल और सेनापति तेजपाल ने मंदिर निर्माण और जीर्णोद्धार के साथ ज्ञान के प्रसार और संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों भाई राजकाज संभालते हुए शास्त्रों की रचना से जुड़े रहे। उन्होंने सात सौ ज्ञानशालाएं चलाने के साथ उनका निरीक्षण भी स्वयं किया। ज्ञान भंडारों के निर्माण में सात सौ करोड़ रुपये खर्च किए गए और आगमों की प्रतियां कश्मीर के ताड़पत्रों पर सोने और चांदी की स्याही से तैयार कराई गईं। आज जब पुस्तक खरीदना और उसका प्रकाशन पहले की तुलना में बहुत आसान है, तब इतिहास के ये उदाहरण समाज को यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि ज्ञान के लिए पूर्वजों ने कितना परिश्रम और संसाधन लगाया। उनके लिए ग्रंथ केवल धार्मिक वस्तु नहीं, बल्कि आने वाले समय की धरोहर थे।

एक नजर

भाजपा नेता उमा भूषण तांती हत्याकांड में मुख्य आरोपी की पत्नी दीपिका कुमारी गिरफ्तार

भागलपुर,एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के श्रीनारायण साह मंडल के अध्यक्ष उमा भूषण तांती उर्फ पप्पू तांती की दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम को पहली बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसआईटी में शामिल महिला पुलिस पदाधिकारियों की टीम ने हत्याकांड की साजिश रचने के आरोप में वार्ड संख्या 51 की वर्तमान पार्षद दीपिका कुमारी को कुतूबगंज से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दीपिका कुमारी इस हत्याकांड के मुख्य नामजद आरोपी, पूर्व पार्षद सह पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि मोदी की पत्नी हैं। पुलिस ने आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। एसआईटी से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि तकनीकी सेल और वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान यह बात प्रमाणित हुई है कि भाजपा नेता की हत्या की इस सनसनीखेज वारदात की साजिश रचने में दीपिका कुमारी भी बराबर की भागीदार थीं। पुलिस इस मामले में अन्य संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अवैध बालू परिवहन पर कार्रवाई, ट्रक जब्त, 8.32 लाख का जुर्माना

किशनगंज,एजेंसी। जिलाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश पर जिले में अवैध खनन एवं खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खान एवं भूतत्व विभाग की टीम ने गलगलिया मद्यनिषेध चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से बालू का परिवहन कर रहे एक ट्रक को जब्त किया। कार्रवाई खान निरीक्षक सुनील कुमार के नेतृत्व में की गई। जांच के दौरान ट्रक चालक से बालू के परिवहन से संबंधित आवश्यक कागजात मांगे गए, लेकिन चालक के पास किसी भी प्रकार का वैध परिवहन दस्तावेज नहीं मिला। इसके बाद टीम ने वाहन को जब्त कर आवश्यक कार्रवाई के लिए गलगलिया थाना को सुपुर्द कर दिया। विभागीय कार्रवाई के तहत जब्त वाहन पर 8.32 लाख रुपये का दंड भी अधिरोपित किया गया है। अधिकारियों के अनुसार बिना वैध परिवहन चालान एवं आवश्यक दस्तावेजों के खनिज का परिवहन नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को खान निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया कि जिले में अवैध खनन, बालू के अवैध उठाव और परिवहन के खिलाफ छापेमारी अभियान लगातार जारी रहेगा। विभिन्न चेक पोस्ट एवं संवेदनशील स्थानों पर वाहनों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन या खनिजों के परिवहन में संलिप्त पाए जाने वाले वाहनों के खिलाफ नियम संगत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध बालू परिवहन में शामिल लोगों में हड़कंप की स्थिति है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि राजस्व की चोरी और अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जांच एवं कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

बाढ़ से भागलपुर त्रस्त, 8.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ की चपेट में, दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष जारी

भागलपुर,एजेंसी। जिले में गंगा नदी के रौद्र रूप धारण करने से बाढ़ की स्थिति अत्यंत भयावह हो गई है। जिले के 111 गांव और 437 वार्ड पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे 2,00,102 परिवारों के 8,56,379 लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। गंगा पार के इलाकों में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। पूर्व मंत्री बुलो मंडल के आवास के आसपास के इलाके में भी अब तक गर्दन तक पानी भरा हुआ है, और पानी कब उतरेगा, इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में मुस्तैद हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 24,812 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। आवागमन और रेस्क्यू के लिए 122 नावों का परिचालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 80 चिकित्सा केंद्र सक्रिय किए गए हैं, जबकि पशुओं की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रभावित पशुओं की संख्या 79,390 तक पहुंच गई है। भूख से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा 317 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही हैं।

सरकारी दावों और प्रयासों के बावजूद जमीन पर बेघर परिवारों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सैकड़ों परिवार ऊंचे स्थानों पर शरण लेकर खानाबदोश की जिंदगी जीने को विवश हैं। बाढ़ के इस संकट ने परिवारों के भीतर पारंपरिक जिम्मेदारियों को भी बदल कर रख दिया है। पीड़ित बताते हैं कि चारों तरफ लबालब पानी भरे होने के कारण बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन गई है। अनहोनी के डर से महिलाएं चौबीसों घंटे बच्चों की निगरानी में जुटी हैं, ताकि वे खेलते हुए पानी की तरफ न चले जाएं। वहीं दूसरी ओर, पुरुष अब परिवार के लिए भोजन जुटाने और पकाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई जगहों पर सामुदायिक किचन चलने के बावजूद लोग अपने स्तर पर भी चूल्हा जलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो किसी जंग से कम नहीं है। चारों तरफ पानी होने के कारण सूखी लकड़ियां मिलना नामुमकिन हो चुका है। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि जो भी जलावन उपलब्ध है, वह पूरी तरह भीगा हुआ है। ऐसे में भीगी लकड़ियों को सुलगने और आग जलाने के लिए घंटों हाथ से पंखा झेलना पड़ता है, तब कहीं जाकर दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है। वहीं बाढ़ का पानी उतरने की धीमी रफ्तार ने ग्रामीणों के सामने आजीविका और सुरक्षा का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है।

हिन्दी केवल संवाद की भाषा नहीं, बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति, सभ्यता है : मुख्यमंत्री

पटना,एजेंसी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को हिन्दी दिवस के अवसर पर कहा कि हिन्दी केवल संवाद की भाषा नहीं, बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति, सभ्यता और समृद्ध साहित्यिक परंपरा की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि हिन्दी के गौरव को समझते हुए इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिन्दी दुनिया में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक है और यह हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाने में बिहार की धरती के अनेक महान साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विद्यापति, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' और जनकवि नागार्जुन जैसे रचनाकारों ने अपनी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से हिन्दी को नई ऊंचाइयां प्रदान कीं और समाज को दिशा दी। उन्होंने कहा कि हिन्दी के साहित्यिक और सांस्कृतिक विस्तार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार में दो दिवसीय हिन्दी साहित्य समागम का आयोजन किया जाएगा। इसमें देशभर के प्रमुख हिन्दी साहित्यकारों, रचनाकारों, कवियों और विद्वानों को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बिहार में बाढ़ की स्थिति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में व्यस्त रहने के बावजूद बिहार की बाढ़ की स्थिति को लेकर संवेदनशील रहने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय टीम बिहार आएगी और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास बाढ़ से होने वाली जन-धन की क्षति को कम करने के साथ ही इस समस्या का स्थायी और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने भी संबोधित किया।

भागलपुर में बाढ़ आपदा की समीक्षा : पानी उतरते ही विशेष टीम करेगी नुकसान का सर्वे, पीड़ितों को नियमों के तहत मिलेगी पूरी सहायता

भागलपुर। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सह भागलपुर जिला प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोमवार को स्थानीय समीक्षा भवन में जिले में बाढ़ और आपदा की स्थिति को लेकर एक विशेष समीक्षा बैठक की। बैठक में क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा करते हुए राहत और बचाव कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, संबंधित विभागों के आला अधिकारी और क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की जमीनी समस्याओं और बाढ़ प्रभावित लोगों की तात्कालिक जरूरतों को प्रभारी मंत्री के सामने प्रमुखता से रखा।

प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन सुझावों और स्थानीय आवश्यकताओं को गंभीरता से लेते हुए राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, जिला प्रशासन सेवाभाव के साथ लगातार काम कर रहा है और प्रभावित इलाकों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर राहत पहुंचाई जा रही है। सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य आपदा प्रभावित लोगों की तकलीफ को कम करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा राहत के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों और गाइडलाइन का राज्य सरकार पूरी तरह पालन कर रही है। गाइडलाइन के तहत जो भी सहायता पीड़ितों को मिलनी है, वह उन्हें निश्चित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की प्राथमिकता है कि आपदा की इस घड़ी में कोई भी पात्र प्रभावित व्यक्ति सहायता से वंचित न रहे। प्रभारी मंत्री ने घोषणा की कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद नुकसान का वास्तविक आकलन करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा। यह टीम प्रभावित क्षेत्रों में जाकर क्षतिग्रस्त घरों, फसलों, सड़कों और सार्वजनिक संपत्तियों का विस्तृत जायजा लेगी। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार पीड़ितों को मुआवजा और सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित लोगों को सुरक्षित रखना और उन्हें जरूरी राहत सामग्री उपलब्ध कराना है। पानी उतरने के बाद क्षति के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। सरकार का दावा है कि नियमों के दायरे में रहकर हर पीड़ित को उसके नुकसान के अनुरूप उचित सहायता दिलाई जाएगी।

अपराधियों के लिए सेफ जोन बना जीबी नगर थाना इलाका, 24 घंटे में दो हत्याओं से दहशत

सीवान,एजेंसी। जिले के जीबी नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों के बढ़ते हौसले ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व सरपंच नयन महतो के पुत्र अविनाश उर्फ धनजी महतो की अपहरण के बाद हत्या की घटना के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पांडेयपुर खमहौरी गांव में 23 वर्षीय रोहित कुमार यादव की चाकू से गोदकर हत्या कर शव फेंक दिया गया। लगातार दो हत्याओं से इलाके में दहशत है और पुलिस के प्रति ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोमवार की सुबह राजकीय मध्य विद्यालय के दक्षिण करीब 50 मीटर की दूरी पर रोहित का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने शव के पास खून के निशान, चाकू और करीब 10 जोड़ी चप्पलें देखीं। सूचना मिलते ही प्रभारी थानाध्यक्ष रामाशंकर साह पुलिस बल और एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल के हालात से प्रथम दृष्टया मृतक और हमलावरों के बीच संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। घटना में दो अन्य युवकों के घायल होने की भी बात सामने आई है।

पुलिस ने परिजनों के मौखिक बयान के आधार पर तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। मृतक अविवाहित था, इसलिए पुलिस प्रेम प्रसंग समेत अन्य बिंदुओं पर जांच कर रही है। तकनीकी सेल की मदद से मोबाइल की भी पड़ताल की जा रही है। लेकिन इन घटनाओं ने पुलिस की गश्ती व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में रात्रि और संध्या गश्ती प्रभावी नहीं है। पुलिस की ओर से वाहनों की कमी का तर्क दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण इसे जिम्मेदारी से बचने का बहाना मान रहे हैं। सबसे गंभीर आरोप सरकारी विद्यालय को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि सूरज ढलते ही विद्यालय के आसपास शराबियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। इसकी सूचना कई बार पुलिस को दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब उसी इलाके में युवक की हत्या ने पुलिस की कथित निष्क्रियता पर सवाल और तीखे कर दिए हैं। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की पुष्टि की, लेकिन अनुसंधान प्रभावित होने का हवाला देते हुए अन्य जानकारी देने से इनकार कर दिया। अब लोगों की नजर पुलिस की कार्रवाई पर है कि वह हत्याकांड का शीघ्र खुलासा कर अपराधियों को जेल भेजती है या जीबी नगर अपराधियों का कथित सेफ जोन बना रहता है।

भागलपुर में 'गणपति बप्पा मोरया' की धूम, कहीं 56 भोग तो कहीं मन रही सिल्वर जुबली

भागलपुर,एजेंसी। जिलेभर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर सोमवार को बप्पा की प्रतिमाएं स्थापित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गयी। सुबह से ही पूजा पंडालों और प्रतिमा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी। भक्तों ने भगवान गणेश को प्रिय लड्डू और मोदक का भोग लगाकर सुख-समृद्धि की कामना की। पूरे शहर में दिनभर 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारे गूंजते रहे। भागलपुर में इस बार गणेश प्रतिमाओं और पंडालों को बेहद आकर्षक और अलग-अलग रूपों में सजाया गया है। कहीं भगवान गणेश भव्य सिंहासन पर विराजे दिखे, तो कहीं वे अपने वाहन मूषक पर सवार नजर आए। पूजा के साथ-साथ कई स्थलों पर भंडारा, भजन-कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो गई है। सोनापट्टी चौक में शर्मा चौक के राजा समिति की ओर से भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा सिंहासन पर स्थापित की गयी है।

महंत विष्णु शर्मा के संचालन में पूजा-अर्चना संपन्न हुई। उन्होंने बताया कि भागलपुर में सबसे पहले गणेश महोत्सव की शुरुआत इसी स्थान से हुई थी। यहां चार दिनों तक अलग-अलग धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, जिसमें मंगलवार को प्रसाद वितरण और बुधवार को भजन-कीर्तन मुख्य आकर्षण होंगे। गणेश पूजा समिति स्वामी विवेकानंद पथ की ओर से जोगसर में स्थापित गणेश प्रतिमा इस बार रंगीन रोशनी और अद्भुत फूलों की सजावट के कारण आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां सोमवार को बप्पा को लड्डू समेत 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया। समिति के सदस्यों ने बताया कि मंगलवार को बप्पा को खिचड़ी और खीर का विशेष भोग लगाया जायेगा और साथ ही भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा। जगन्नाथ मंदिर में भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के अवसर पर पारंपरिक गणेश पूजा की गयी। परबत्ती में सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान गणेश की प्रतिमा की प्राण-प्रतिष्ठा की गयी। शाम को यहां भव्य महाआरती का आयोजन हुआ, जिसके बाद देर रात तक भजन-कीर्तन का दौर चलता रहा। सिकंदरपुर रोड स्थित गजानंद क्लब के लिए यह साल बेहद खास है। क्लब की ओर से इस वर्ष गणेश उत्सव की 25वीं वर्षगांठ मनायी जा रही है। इसके अलावा, वारसलीगंज स्थित बजरंगबली स्थान परिसर में भी मां शेरावाली क्लब की ओर से बप्पा की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की गयी।

भागलपुर में बाढ़ ने छीनी अंतिम विदाई की जगह, सड़क किनारे सज रहीं चिताएं

भागलपुर,एजेंसी। भागलपुर में गंगा का उफान अब सिर्फ घरों, खेतों और सड़कों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बाढ़ ने इंसान की अंतिम विदाई की जगह तक छीन ली है। क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति इस कदर विकट हो चुकी है कि बरारी श्मशान घाट पूरी तरह पानी में डूब चुका है और लोग मजबूरी में मुख्य सड़क के किनारे ऊंची जगहों पर अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने को विवश हैं। जहाँ कभी अंतिम क्रिया के लिए विधिवत लकड़ियाँ सजती थीं, वहाँ अब चारों तरफ सिर्फ गंगा का पानी पसरा हुआ है।

श्मशान घाट का एक बड़ा हिस्सा और वहां बना शेड पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ऐसे में शव लेकर पहुंचने वाले परिजनों को सड़क किनारे ही कोई ऊंची और अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह तलाशनी पड़ रही है। एक तरफ गंगा का बढ़ता पानी, दूसरी तरफ सड़क पर जलती चिता और बीच में वाहनों की आवाजाही—भागलपुर में बाढ़ की यह विचलित कर देने वाली तस्वीर प्रशासनिक व्यवस्था की एक बड़ी लाचारी को उजागर कर रही है। बारिश और बाढ़ के इस दौर में अपनों को मुखाग्नि देना भी किसी कड़ी परीक्षा से कम नहीं रह गया है। बाढ़ के पानी के कारण सूखी लकड़ियां मिलना एक बड़ी चुनौती बन गया है। अमरपुर से अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोगों ने बताया कि सामान्य दिनों में श्मशान घाट के आसपास लकड़ी और अन्य पूजन सामग्री आसानी से मिल जाती थी, लेकिन बाढ़ ने पूरी व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है। अब परिजन को शव घाट तक लाने, लकड़ी जुटाने, चिता सजाने और गीली लकड़ियों के बीच चिता जलाने के लिए पानी, कीचड़ और भारी यातायात के बीच जूझना पड़ रहा है। बरारी मुख्य सड़क के किनारे हो रहे अंतिम संस्कार का सीधा असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों और स्थानीय लोगों को चिताओं से उठते घने धुएं के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। हालांकि, इन दृश्यों के पीछे सबसे बड़ी पीड़ा उन परिवारों की है, जो इस संकट की घड़ी में भी अपने प्रियजनों को सम्मानजनक विदाई देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहां बाढ़ के बीच लकड़ी खरीदने से लेकर चिता जलाने तक हर कदम पर आफत है। पानी और कीचड़ के बीच किसी तरह धार्मिक रीतियों को पूरा करना पड़ रहा है, क्योंकि मृत्यु किसी बाढ़ का इंतजार नहीं करती और अंतिम संस्कार को टाला नहीं जा सकता। उधर गंगा के बढ़ते जलस्तर का कहर सिर्फ बरारी तक सीमित नहीं है। सुल्तानगंज का श्मशान घाट भी पूरी तरह पानी से घिरकर टापू में तब्दील हो चुका है। घाट के चारों तरफ पानी भर जाने के कारण वहाँ भी शवों के अंतिम संस्कार को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जब तक बाढ़ का पानी कम नहीं होता, तब तक दाह संस्कार के लिए किसी वैकल्पिक और सुरक्षित स्थान की तत्काल व्यवस्था की जाए।

कपड़ा दुकान के गोदाम में भीषण आग, 60 लाख की संपत्ति राख

नवादा। नवादा शहर के कलाली रोड स्थित अमन ड्रेसेज कपड़ा दुकान के गोदाम में सोमवार को अचानक भीषण आग लग जाने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने गोदाम में रखे कपड़ों और अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और घना धुआं उठता देख आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। अगलगी की इस घटना में करीब 50 से 60 लाख रुपये मूल्य के कपड़े जलकर राख होने की आशंका जताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सोमवार को अचानक गोदाम की ओर से धुआं निकलता दिखाई दिया। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गईं। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। गोदाम में बड़ी मात्रा में कपड़े रखे होने के कारण आग तेजी से फैल गई। कपड़ा और अन्य ज्वलनशील सामान होने से आग की लपटें काफी तेज थीं। आग बुझाने के दौरान आसपास के लोगों को भी सुरक्षित दूरी पर रखा गया। समाचार लिखे जाने तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे थे और आग पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। दुकान संचालक एवं स्थानीय लोगों के अनुसार, गोदाम में रखे कपड़ों की कीमत करीब 50 से 60 लाख रुपये के बीच बताई जा रही है। आग की तीव्रता को देखते हुए गोदाम में रखा काफी सामान जलकर नष्ट होने की आशंका है। हालांकि, अगलगी में वास्तविक रूप से कितने रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है, इसका आकलन आग पूरी तरह बुझने और क्षतिग्रस्त सामान की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना के बाद कलाली रोड में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आसपास के दुकानदारों में भी आग को लेकर चिंता देखी गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य कारण से लगी हो सकती है। अग्निशमन विभाग एवं संबंधित अधिकारियों द्वारा घटना की जांच के बाद ही आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

एक नजर

वरुण अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर, एशियाई खेलों में हिस्सा लेना भी संदिग्ध

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती सोमवार को चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज से बाहर हो गए और इस चोट के चलते आगामी एशियाई खेलों में उनके खेलने पर भी संशय पैदा हो गया है। चक्रवर्ती हाल में पैर की मांसपेशियों में खिंचाव की चोट से उबरे थे जो उन्हें जुलाई में इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी थी। उन्होंने रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में एक विकेट लिया था। भारत ने यह मैच आसानी से जीता था और चक्रवर्ती ने अपने चार ओवरों में महज 16 रन दिए थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक सूत्र ने कहा, ''यह नई चोट है। वह सीरीज से बाहर हो गए हैं। हाल के दिनों में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' में खिलाड़ियों की चोटों के बार-बार सामने आने के कारण वहां की चोट प्रबंधन व्यवस्था सवालों के घेरे में रही है। चक्रवर्ती की ताजा चोट भी इसी सिलसिले का एक और उदाहरण है। इस नई चोट के कारण 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों में चक्रवर्ती का हिस्सा लेना भी संदिग्ध है।

'मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेना हमारे लिए बेइज्जती होती', ऋचा घोष के पिता ने किया भारतीय टीम के फैसले का समर्थन

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय टीम ने रविवार को फाइनल में श्रीलंका को हराकर विमेंस एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम किया। हालांकि, पुरुष टीम की तरह भारतीय महिला टीम ने भी एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भारतीय टीम के इस फैसले का ऋचा घोष के पिता मानबेंद्र घोष ने भी समर्थन किया है। मानबेंद्र घोष ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रॉफी का बहिष्कार कर रहा है। ट्रॉफी तो हमेशा हमारी ही है ऐसी फोर्स से जुड़े होने के कारण बदनाम हुए व्यक्ति से ट्रॉफी लेना, जिन्होंने हमें कई तरह से नुकसान पहुंचाया है, जिनमें से एक पहलगाम की घटना भी है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इससे हमारे जख्म भर सकते हैं। ऐसे इंसान से ट्रॉफी लेना हमारे लिए बेइज्जती होती। मुझे लगता है कि भारतीय टीम का फैसला एकदम सही था। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज के पिता ने टीम के प्रदर्शन की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, 'फाइनल जीतना ही सबसे बड़ी बात होती है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। इसी वजह से जब लड़कियों ने फाइनल जीता, तो हम बहुत खुश और उत्साहित थे। नहीं, यह किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। उनमें से ज्यादातर, बल्कि सभी ने अच्छा खेला। जिस खिलाड़ी को भी मौका मिला, उसने कोशिश की और अपनी भूमिका निभाई। हम बस यही तो चाहते हैं। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन दमदार रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 183 रन स्कोबोर्ड पर लगाए। टीम की ओर से शेफाली वर्मा ने 39 गेंदों में 68 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि स्मृति मंधाना ने 59 रनों का योगदान दिया। बल्लेबाजों के बाद दीप्ति शर्मा और श्री चरणी की स्पिन जोड़ी ने मिलकर श्रीलंका की पूरी टीम को सिर्फ 111 रनों पर ऑलआउट किया। दीप्ति ने 3 और चरणी ने 4 विकेट चटकाए। भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप के खिताब पर कब्जा जमाया।

विमेंस एशिया कप : खिताबी जीत के बाद क्रांति गौड़ पर आईसीसी ने लगाया जुर्माना

दुबई,एजेंसी। भारत ने रविवार को श्रीलंका के खिलाफ विमेंस एशिया कप 2026 का फाइनल 72 रन से अपने नाम किया, लेकिन इस जीत के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने सोमवार को बताया कि क्रांति गौड़ ने खिलाड़ियों की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 का उल्लंघन किया है, जिसमें ऐसी भाषा, हरकत या इशारे शामिल हैं जो किसी बल्लेबाज के आउट होने पर उनका अपमान करते हैं या

आक्रामक प्रतिक्रिया भड़का सकते हैं। यह घटना श्रीलंका की पारी के शुरुआती ओवर की है, जब क्रांति ने ओपनर इमेशा दुलानी को बोल्ड करने के बाद पवेलियन की ओर इशारा किया। मैच फीस में कटौती के अलावा, क्रांति के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ा गया। यह 24 महीने की अवधि में उनका पहला अपराध था। क्रांति पर यह आरोप ऑन-फील्ड अंपायर सलीमा इम्तियाज और शथिरा जाकिर जेसी ने आरोप लगाए थे। इसमें थर्ड अंपायर रोकेया सुल्ताना और चौथे अंपायर हुमैरा फराह भी शामिल थीं, जिसके बाद आईसीसी इंटरनेशनल पैनल की मैच रेफरी सुप्रिया रानी दास ने यह सजा दी। क्रांति ने आरोप स्वीकारते करते हुए सजा मान ली, जिससे औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। आईसीसी के नियमों के तहत, लेवल 1 के अपराधों के लिए खिलाड़ी की मैच फीस का अधिकतम 50 प्रतिशत जुर्माना और दो तक डिमेरिट प्वाइंट्स दिए जा सकते हैं। एक अलग फैसले में, शुक्रवार को श्रीलंका के हाथों सेमीफाइनल में हार के दौरान धीमी ओवर-रेट बनाए रखने के लिए पाकिस्तान पर मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया, क्योंकि समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद भी वे अपने लक्ष्य से एक ओवर पीछे पाए गए। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.22 के तहत, अगर कोई टीम तय समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर पाती, तो खिलाड़ियों की मैच फीस का 5 प्रतिशत हिस्सा हर ओवर के लिए काट लिया जाता है। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने अपनी गलती मानते हुए सजा स्वीकार कर ली है।

मांडविया ने एचआईएल के पुनरुद्धार की योजना बनाने को कहा, पांच सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश

नई दिल्ली,एजेंसी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को हॉकी इंडिया और हॉकी इंडिया लीग (एचआईएल) के फ्रेंचाइजी मालिकों से आर्थिक संकट से जूझ रही लीग की वित्तीय व्यावहारिकता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक खाका तैयार करने को कहा और इसके लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करने का निर्देश दिया। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मांडविया ने हॉकी इंडिया के अधिकारियों और एचआईएल फ्रेंचाइजी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जिसमें उन्हें प्रतियोगिता से जुड़ी चिंताओं से अवगत कराया गया। सूत्र ने कहा, ''खेल मंत्री ने सभी हितधारकों के साथ बैठक की और उन्हें एचआईएल से जुड़ी चिंताओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने हॉकी इंडिया के अधिकारियों को लीग की वित्तीय व्यावहारिकता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए योजना पर काम करने का निर्देश दिया।

सूत्र ने कहा, ''मंत्री ने हॉकी इंडिया से एचआईएल के पुनरुद्धार के लिए व्यापक योजना तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करने को भी कहा। समिति में हॉकी इंडिया और फ्रेंचाइजी के दो-दो प्रतिनिधि तथा खेल मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होगा। उन्होंने कहा, ''मंत्री ने हितधारकों को प्राथमिकता के आधार पर लीग के संचालन मॉडल, वित्तीय मॉडल और ढांचे पर काम करने का निर्देश दिया। समिति को तय समय सीमा में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपने को कहा गया है। बैठक में हैदराबाद तूफांस, वेदांता कलिंग लांसर्स, जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब, शाची बंगाल टाइगर्स, एएलपी पाइपर्स, जेके सीमेंट्स और नई बेंगलुरु फ्रेंचाइजी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सात साल के अंतराल के बाद

पिछले साल एचआईएल को फिर शुरू किया गया था लेकिन इसके बाद से लीग की वित्तीय स्थिरता और फ्रेंचाइजी की भागीदारी को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं जिससे इसके दीर्घकालिक भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। खेल सचिव और भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के महानिदेशक हरि रंजन राव, टॉप्स के सीईओ एनएस जौहल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक करीब एक घंटे चली। हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह और कोषाध्यक्ष शेखर जे मनोहरन बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए जबकि आर के श्रीवास्तव की शक्तियां हाल में कम किए जाने के बाद रणजीत गिल ने कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में बैठक में हिस्सा लिया।

यह बैठक हॉकी इंडिया के भीतर जारी सत्ता संघर्ष के बीच हुई है। अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी कर उन्हें महानिदेशक के अधिकारों का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया है। हालांकि श्रीवास्तव ने सोमवार को मोहाली में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक आधिकारिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह और कार्यकारी बोर्ड के सदस्य आर पी सिंह भी मौजूद थे जहां 2026 पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की तारीखों और आयोजन स्थलों की घोषणा की गई।

'साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं', बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास और लक्ष्मण ने दी चैंपियन बनने पर भारतीय टीम को बधाई

नई दिल्ली। भारतीय महिला टीम ने रविवार को रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप के खिताब को अपने नाम किया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में हरमनप्रीत एंड कंपनी ने श्रीलंका को 72 रनों से रौंदा। इस जीत को टीम के दबदबे और सबसे ऊंचे लेवल पर लगातार मुकाबला करने में सक्षम टीम बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष मिथुन मन्हास और पूर्व भारतीय क्रिकेटर व सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के चीफ वीवीएस लक्ष्मण ने चैंपियन बनने पर भारतीय टीम को बधाई दी है।

भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए एशिया कप के खिताब पर कब्जा जमाया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने एशिया कप 2024 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ मिली हार का हिसाब भी चुकता कर लिया। बीसीसीआई अध्यक्ष मन्हास ने भारत के इस अभियान में टीम की सामूहिक कोशिशों की तारीफ की और उस एकता का जिक्र किया जिसने टीम को अजेय रहने और आखिरकार ट्रॉफी जीतने में मदद की। मन्हास ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं, एशिया कप जीतने पर भारतीय महिला टीम की हर सदस्य को बहुत-बहुत बधाई। पूरे टूर्नामेंट में शानदार दबदबा रहा। भारत की इस खिताबी जीत में टीम के सभी विभागों का योगदान रहा। फाइनल में शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की रिकॉर्ड 129 रनों की ओपनिंग साझेदारी ने भारत को 183/5 के स्कोर तक पहुंचाया, जिसके बाद गेंदबाजों ने श्रीलंका के लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश को नाकाम कर दिया और उन्हें 111 रनों पर समेट दिया।

श्री चरणी ने 4-20 के आंकड़े के साथ गेंदबाजी की कमान संभाली, जबकि दीप्ति शर्मा ने तीन विकेट लिए और भारत ने 72 रनों से शानदार जीत दर्ज की। लक्ष्मण ने इस जीत को सिर्फ एक उपलब्धि नहीं माना, बल्कि इसे भारत के विश्व स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया।

वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा, 'शानदार एशिया कप जीत के लिए महिला टीम को बधाई। यह एक मजबूत, निडर और विश्व स्तरीय टीम बनाने की दिशा में एक और अहम कदम है, जिसका मकसद वैश्विक मंच पर दबदबा बनाना, लगातार जीतना और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करना है।'

स्टीव स्मिथ ने एशेज 2027 खेलने पर जताया संदेह, एलए ओलंपिक 2028 पर नजर

मालाहाइड। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने एशेज सीरीज 2027 खेलने को लेकर अनिश्चितता जताई है, जिसका आयोजन इंग्लैंड में होगा। स्मिथ ने बताया कि वह फिलहाल अपने टेस्ट करियर को सीरीज-दर-सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि उनका लक्ष्य 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में हिस्सा लेना भी है। 37 वर्षीय स्मिथ अभी यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ईटीपीएल) में एम्स्टर्डम फ्लेम्स की तरफ से खेल रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने टेस्ट करियर में 125 मैच खेलते हुए 37 शतक लगाए हैं। वह फिलहाल इंग्लैंड के हैरी ब्रूक के बाद पुरुषों की टेस्ट रैंकिंग में दूसरे नंबर के बल्लेबाज हैं।

स्मिथ ने सोमवार को 'द टेलीग्राफ' से कहा, 'मुझे अभी यह भी नहीं पता कि मैं तब वहां रहूंगा या नहीं। मैं सीरीज-दर-सीरीज सोच रहा हूं, जैसा कि मैं कुछ समय से कर रहा हूं, और वह समय अभी मेरे लिए काफी दूर है। मैं वहां जीतना चाहूंगा या वहां जीत चुका होता, लेकिन देखते हैं कि क्या ऐसा हो पाता है। अभी शायद ओलंपिक्स ही (लक्ष्य के तौर पर) है, जिसका हिस्सा बनने की कोशिश करनी है। यहां एम्स्टर्डम के साथ खेलने की एक वजह यह भी थी कि मैं जितना हो सके टी20 क्रिकेट खेलना जारी रख सकूं। हालांकि, स्मिथ ने संन्यास की कोई तारीख निश्चित नहीं की है, लेकिन उन्होंने माना कि उनके खेलने का बचा हुआ समय ज्यादातर फ्रेंचाइजी टी20 क्रिकेट की ओर झुका रहेगा। उन्होंने कहा, 'मुझे अभी भी लगता है कि मैं कुछ समय तक टी20 क्रिकेट खेल सकता हूं। मेरे खेलने के बाद आगे क्या होगा? मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन हां, उम्मीद है कि खेलने के लिए थोड़ा और समय बचा है। मैंने खेल में बहुत कुछ हासिल किया है। पिछले 15 साल या उसके आस-पास का सफर बहुत शानदार रहा है। मैं इसका आनंद ले रहा हूं, इसलिए मेरे पास कोई आखिरी तारीख नहीं है, हम इंतजार करेंगे और देखेंगे, लेकिन यह एक अच्छा सफर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम अक्टूबर में तीन टेस्ट मुकाबलों की सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी। साल 2018 में हुए बॉल-टेम्परिंग विवाद के कारण स्मिथ पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से 12 महीने का बैन लगा था, जिसके बाद यह साउथ अफ्रीका में उनका पहला टेस्ट दौरा होगा। स्मिथ ने कहा, 'मेरे लिए तो यह बस एक और सीरीज है। वह सब बहुत पहले हुआ था, और हमने तब से काफी क्रिकेट खेला है। हम उसके बाद वनडे मुकाबलों के लिए साउथ अफ्रीका भी गए हैं। इस समय साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम है, उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हमें हराया था।

विमेंस एशिया कप के साथ भारत ने 'एशियन गेम्स' के लिए भी बेहतरीन तैयारी की: देवजीत सैकिया

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय टीम ने रविवार को दुबई में खेले गए 'विमेंस एशिया कप 2026' के फाइनल में श्रीलंका को 72 रन से रौंदकर रिकॉर्ड 8वीं बार खिताब जीता। 'विमेन इन ब्लू' के प्रदर्शन से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष देवजीत सैकिया बहुत खुश हैं। उनका मानना है कि इस टूर्नामेंट के साथ भारत ने एशियन गेम्स की शानदार तैयारी की है।

सैकिया ने सोमवार को पत्रकारों से कहा, 'भारतीय महिला टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के सभी मैच एकतरफा रहे हैं। एशिया कप के साथ भारतीय टीम ने एशियन गेम्स 2026 के लिए भी बेहतरीन तैयारी की है। मैं टीम और सपोर्ट स्टाफ को बधाई देता हूं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जीत के इस सिलसिले को जापान (एशियन गेम्स) तक ले जाएं। सैकिया ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सफलता का श्रेय बोर्ड के पूर्व सचिव जय शाह को देते हुए कहा, 'जय शाह ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा दिया है। आज के दौर में भारतीय महिला टीम हर टूर्नामेंट में चैंपियन बनने लगी है, इसका श्रेय जय शाह को जाता है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को उसकी सरजमीं पर मात दी। जब जय शाह बीसीसीआई के सचिव थे, उस समय विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) शुरू किया। इसके साथ ही समान वेतन को लाया गया। इन महत्वपूर्ण फैसलों का असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन में नजर आता है। खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं ली। इस मामले पर देवजीत सैकिया ने कहा, 'टूर्नामेंट जीतना बहुत अच्छी बात है, जबकि

ट्रॉफी नहीं लेना दूसरी बात है। ट्रॉफी नहीं लेकर हमने कोई विवाद पैदा नहीं किया है। हमने इसके बारे में पहले ही बता दिया था। पहलगाम हमले के बाद जो कुछ हुआ, सभी को मालूम है। उस समय हमने अपनी बात साफ तौर पर रख दी थी और अपने रुख पर कायम रहे। हमने पहले ही बता दिया था कि पुरस्कार वितरण का जो तरीका तय किया गया था, वह हमें पसंद नहीं था। हमने उनके चेयरमैन को भी पहले से बता दिया था कि अगर पुरस्कार उसी तरीके से दिए जाएंगे, तो हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। जब वे अपने फैसले पर कायम रहे, तो हमने भी ट्रॉफी नहीं ली। हालांकि, हम उसे बाद में ले सकते हैं। 'यह फैसला पूरी तरह से बीसीसीआई का था। इस मुद्दे पर हमने आपस में चर्चा करके पहले ही अपना रुख तय कर लिया था और वही रुख आज भी कायम है। चाहे खिलाड़ी हों, टीम प्रबंधन हो या बीसीसीआई के अधिकारी, सभी की राय एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि खिलाड़ियों का कोई अलग फैसला हो और बीसीसीआई का अलग। हम सभी का निर्णय एक ही है और बीसीसीआई की नीति के अनुसार ही सभी कदम उठाए जाते हैं।'

पाकिस्तान का हाल हुआ बेहाल, क्लीन स्वीप के बाद आईसीसी ने लगाया जुर्माना, 11 डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स भी काटे

नई दिल्ली,एजेंसी। इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में हुए तीसरे टेस्ट में धीमी ओवर गति बनाए रखने के कारण पाकिस्तान को दोहरी सजा मिली है। इसके चलते टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) की प्वाइंट्स टेबल में नुकसान हुआ है और उनका जीत प्रतिशत घटकर 10 प्रतिशत से भी नीचे पहुंच गया है।

आईसीसी ने बताया कि बर्मिंघम में इंग्लैंड से 8 विकेट से हार के दौरान, समय की छूट को ध्यान में रखने के बाद भी लक्ष्य से 11 ओवर कम होने के कारण पाकिस्तान पर मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और उनके 11 डब्ल्यूटीसी प्वाइंट भी काट लिए गए हैं।पाकिस्तान टीम को ऑन-फील्ड अंपायर पॉल राइफेल, क्रिस गैफनी, तीसरे अंपायर अल्लाहउद्दीन पालेकर और चौथे अंपायर रसेल वॉरेन ने दोषी पाया है। एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल के मैच रेफरी रंजन मदुगले ने इंग्लैंड के खिलाफ 0-3 से बुरी तरह हारने के बाद बाबर आजम की टीम को यह सजा सुनाई है। इस सजा का पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। बर्मिंघम टेस्ट में हार के बाद टीम का पहले ही डब्ल्यूटीसी प्वाइंट्स टेबल में जीत प्रतिशत 14.81 हो गया था और टीम सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई थी। अब 11 अंक काटे जाने के बाद पाकिस्तान का जीत प्रतिशत घटकर सिर्फ 4.63 प्रतिशत रह गया है। इस कटौती के बाद टीम के पास 9 मैचों से केवल पांच अंक बचे हैं। मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में पाकिस्तान ने दो मैच

जीते हैं और सात हारे हैं लेकिन धीमी ओवर गति (स्लो ओवर रेट) के कारण उसे अपने 24 प्वाइंट्स में से 19 प्वाइंट गंवाने पड़े हैं। 11 प्वाइंट की इस कटौती से पहले, इस साल मई में बांग्लादेश के खिलाफ ढाका टेस्ट में धीमी ओवर गति के कारण पाकिस्तान के आठ प्वाइंट भी काटे गए थे। ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। बांग्लादेश के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ के बाद उनके पास 96 प्वाइंट हैं और उनका जीत प्रतिशत 80 है। साउथ अफ्रीका 36 प्वाइंट और 75 के जीत प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है। 72.22 के जीत प्रतिशत के साथ न्यूजीलैंड तीसरे और बांग्लादेश 55.56 के जीत प्रतिशत के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है।

एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 27 अक्टूबर से, मोहाली और जालंधर करेगा मेजबानी

मोहाली। हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी-2026 का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पंजाब के मोहाली और जालंधर में किया जाएगा। टूर्नामेंट की तारीखों की आधिकारिक घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को मोहाली में की। महाद्वीपीय स्तर के इस प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट के मुकाबले मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम और जालंधर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। जालंधर में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक उद्घाटन समारोह के साथ लीग चरण के सभी मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद टूर्नामेंट मोहाली पहुंचेगा, जहां 4 नवंबर को दोनों सेमीफाइनल और 5 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ऐतिहासिक हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2026 पंजाब के लिए केवल एक हॉकी टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि यह उस खेल की भावनात्मक घर वापसी है, जिसने भारतीय हॉकी के कई दिग्गजों को जन्म दिया है। उन्होंने कहा, 'पहली बार पंजाब अपनी धरती पर इस स्तर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। पंजाब सरकार इसे खिलाड़ियों, दर्शकों और भारत तथा दुनिया भर के हॉकी प्रेमियों के लिए यादगार खेल आयोजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह, महानिदेशक कमांडर आरके श्रीवास्तव, कार्यकारी बोर्ड सदस्य आरपी सिंह और हॉकी पंजाब के अध्यक्ष नितिन कोहली भी मौजूद रहे। टूर्नामेंट में एशिया की शीर्ष हॉकी टीमों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, चीन और जापान को प्रतिभागी टीमों में शामिल किया गया है, जबकि ओमान और बांग्लादेश रिजर्व टीमों के रूप में हैं। हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी एशियाई हॉकी महासंघ के कैलेंडर के प्रमुख टूर्नामेंटों में शामिल है। यह महाद्वीप की शीर्ष टीमों को उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा का मंच प्रदान करता है। 2026 संस्करण के जरिए पंजाब की समृद्ध हॉकी विरासत और खेल में उसके योगदान को भी प्रदर्शित किया जाएगा। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि पंजाब की हॉकी विरासत बेहद गौरवशाली है और हमें खुशी है कि मोहाली और जालंधर हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की मेजबानी करेंगे। हम पंजाब सरकार के सहयोग और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह ने कहा, 'हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2026 की तारीखों की घोषणा पंजाब में यादगार टूर्नामेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान के सहयोग और हॉकी के प्रति प्रतिबद्धता के लिए आभारी हैं। मोहाली और जालंधर की समृद्ध हॉकी संस्कृति एशिया की शीर्ष टीमों के लिए शानदार मंच उपलब्ध कराएगी।'

एक नजर

ट्रंप ने ईंधन की कीमतों में उछाल के लिए ज़ेलेंस्की को ज़िम्मेदार ठहराया

वॉशिंगटन,एजेंसी। अमेरिका में डीज़ल की कीमतों में तेज़ उछाल के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप का आरोप है कि रूस की तेल रिफाइनरियों और ईंधन प्रतिष्ठानों पर यूक्रेन के लगातार हमलों के कारण वैश्विक ईंधन बाजार पर दबाव बढ़ रहा है। रूस की अंतरराष्ट्रीय समाचार टेलीविजन नेटवर्क रशिया टुडे (आरटी) के मुताबिक, अमेरिका में डीज़ल की राष्ट्रीय औसत कीमत इस सप्ताह पहली बार 6 डॉलर प्रति गैलन के पार पहुंच गई। शुक्रवार को कीमत 6 डॉलर से अधिक दर्ज की गई, जबकि एक सप्ताह पहले यह करीब 5.85 डॉलर प्रति गैलन थी। पिछले साल इसी अवधि में डीज़ल की कीमत लगभग 3.71 डॉलर प्रति गैलन थी। आयरलैंड की यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ज़ेलेंस्की के सामने डीज़ल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने यूक्रेनी नेतृत्व से रूस में डीज़ल उत्पादन से जुड़े ठिकानों को निशाना नहीं बनाने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के पास रूस में हमला करने के लिए कई दूसरे लक्ष्य हैं, लेकिन डीज़ल ईंधन से जुड़े प्रतिष्ठानों पर हमले वैश्विक स्तर पर ईंधन आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात से भी इनकार किया कि डीज़ल की कीमतों में मौजूदा तेजी मुख्य रूप से मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और अमेरिका-ईरान तनाव के कारण है। उन्होंने इसके बजाय रूस-यूक्रेन युद्ध और यूक्रेनी हमलों को कीमतों में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण बताया। हालांकि, बाजार के जानकारों के मुताबिक डीज़ल की कीमतों में हालिया उछाल के पीछे मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी अहम कारण हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव ने भी अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अनिश्चितता बढ़ाई है। यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूस की तेल रिफाइनरियों और पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों पर कई हमले किए हैं। इन हमलों से रूस के कुछ हिस्सों में ईंधन की उपलब्धता प्रभावित हुई और कीमतों में बढ़ोतरी हुई। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन हमलों का असर गैसोलीन पर डीज़ल की तुलना में अधिक रहा है। घरेलू बाजार में ईंधन की कमी और बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए रूस ने गैसोलीन, डीज़ल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर अस्थाई प्रतिबंध लगाए हैं। डीज़ल के निर्यात पर प्रतिबंध पहले लगाया गया था, जबकि बाद में इसे गैसोलीन उत्पादकों तक भी बढ़ाया गया। डीज़ल निर्यात पर मौजूदा प्रतिबंध को सितंबर के अंत तक जारी रखने की बात कही गई है और इसके आगे बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।

दक्षिण कोरिया-जापान-अमेरिका ड्रिल के बाद उत्तर कोरिया का पलटवार, किया 'स्ट्राइक ड्रिल'

सियोल। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच पांच दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास के खत्म होने के बाद उत्तर कोरिया ने आर्टिलरी और मिसाइल इकाइयों के साथ बड़े पैमाने पर 'फायरपावर स्ट्राइक ड्रिल' की। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया ने सोमवार को इस सैन्य अभ्यास की जानकारी दी। दक्षिण कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी योनहाप के अनुसार, यह रिपोर्ट दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ (जेसीएस) के उस बयान के दो दिन बाद आई है, जिसमें बताया गया था कि उत्तर कोरिया ने वोनसान इलाके से ईस्ट सी की ओर कई शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। गौरतलब है कि, बीते 12 सितंबर को कोरियन पीपुल्स आर्मी की लंबी दूरी की आर्टिलरी और मिसाइल इकाइयों ने संयुक्त फायरपावर अटैक ड्रिल में हिस्सा लिया। अभ्यास में पांच आर्टिलरी और मिसाइल संयुक्त इकाइयों से चुनी गई सब-यूनिट्स शामिल थीं। इस दौरान कई आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें कई प्रकार के अटैक ड्रोन, टैक्टिकल क्रूज़ मिसाइलें, बड़े कैलिबर वाले थर्मल-प्रेशर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल थीं।

उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि सभी स्ट्राइक हथियार प्रणालियों ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को 100 प्रतिशत सटीकता के साथ निशाना बनाया। उत्तर कोरिया ने इस अभ्यास को अपनी फायरपावर और विभिन्न सैन्य इकाइयों के बीच समन्वय की क्षमता का प्रदर्शन बताया। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग-उन इस ड्रिल में मौजूद नहीं थे। अभ्यास की निगरानी उत्तर कोरिया के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन पाक जोंग-चोन ने की। वहीं, उत्तर कोरियाई सेना के आर्टिलरी ब्यूरो के डायरेक्टर यू चांग-सन ने कहा कि इस तरह के व्यावहारिक अभ्यास से दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी और सैन्य विशेषज्ञता को मजबूत किया जाएगा। शनिवार का मिसाइल लॉन्च इस साल उत्तर कोरिया का 13वां बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण माना जा रहा है। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के आकलन के मुताबिक, दागी गई मिसाइलें ह्वासोंग-11 सीरीज की शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हो सकती हैं। इसके अलावा 600 मिलीमीटर के सुपर-लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से भी गोले दागे जाने की बात सामने आई है। उत्तर कोरिया आम तौर पर मिसाइल लॉन्च के अगले दिन उसकी जानकारी सार्वजनिक करता है। हालांकि, इस बार रिपोर्ट केवल चोसुन इल्बो में प्रकाशित हुई और घरेलू दर्शकों के लिए प्रमुख मीडिया आउटलेट रोडोंग सिनमुन में इसे जगह नहीं दी गई। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पूर्व और दक्षिण में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में अपना पांच दिवसीय 'फ्रीडम एज' सैन्य अभ्यास पूरा किया था। उत्तर कोरिया ने इस अभ्यास की कड़ी आलोचना की है। उसके रक्षा मंत्री किम सोंग-गी ने अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य अभ्यासों को उकसावे की कार्रवाई बताते हुए जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी। हालांकि, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने पिछले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश के बाद अपना वार्षिक 'उल्ची फ्रीडम शील्ड' अभ्यास कम कर दिया था, लेकिन अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का 'फ्रीडम एज' अभ्यास तय कार्यक्रम के अनुसार हुआ।

नेपाल : डीएनए से 1,230 शवों की हुई पहचान, बाढ़ के 19 दिन बाद भी हजारों लोग लापता

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के 18 दिन बाद भी हजारों लोग लापता हैं। लंबे समय से अपनों का इंतजार कर रहे परिवारों को अब तक न तो उनके जिंदा होने की खबर मिली है और न ही शव का पता चल पाया है। बाढ़ में मिले ज्यादातर शवों की हालत इतनी खराब है कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब लापता लोगों के परिवारों के लिए डीएनए जांच ही आखिरी उम्मीद बन गई है। सोमवार सुबह 10 बजे तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1,388 शव बरामद किए जा चुके थे। इनमें से केवल 103 शवों की पहचान हो पाई है और उन्हें उनके परिजनों को सौंपा गया है। वहीं, पहचान नहीं हो पाने वाले 1,285 शवों को दफना दिया गया है। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले के मुताबिक, शवों की पहचान में मदद के लिए पुलिस ने अपनी वेबसाइट पर 1,334 शवों की तस्वीरें अपलोड की हैं। इससे पहले भी कुछ परिवारों ने वेबसाइट पर तस्वीरें देखकर अपने परिजनों के शव की पहचान की थी। बाढ़ के बाद 5 हजार से अधिक लोगों के लापता होने की जानकारी है। जिन परिवारों को अब तक अपनों का कोई सुराग नहीं मिला है, वे डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस के अनुसार, डीएनए मिलान के लिए अब तक 1,779 परिजनों के रक्त के नमूने लिए जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

पहचान नहीं हो पाने वाले शवों को फिलहाल जमीन में दफनाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, डीएनए मैच होने पर दफनाए गए शवों को निकालकर संबंधित परिवार को सौंपने की तैयारी की जाएगी। लंबे इंतजार के बाद कुछ परिवारों ने

अपने परिजनों के जिंदा मिलने की उम्मीद छोड़ दी है। उन्होंने कुश का शव बनाकर अंतिम संस्कार तक कर दिया है। हालांकि, कई परिवार ऐसे भी हैं जो डीएनए जांच के बाद अपने परिजन का शव मिलने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता काफ्ले के अनुसार, अब तक करीब 400 शवों की डीएनए रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। शवों से नमूने लेकर काठमांडू के सामाखुशी स्थित नेपाल पुलिस की विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला और नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (एनएएसटी) की प्रयोगशाला में डीएनए जांच की जा रही है। राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुख और डीएनए विशेषज्ञ निराजन थापा के मुताबिक, मौजूदा क्षमता के हिसाब से सभी शवों की डीएनए जांच पूरी करने में करीब ढाई महीने तक का समय लग सकता है। उन्होंने बताया कि अभी करीब 1,200 से 1,300 शवों की डीएनए जांच की जानी है। एनएएसटी और राष्ट्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मिलकर हर सप्ताह करीब 250 शवों और 400 परिजनों के रक्त नमूनों की जांच कर रहे हैं। हालांकि, कुछ शवों के डीएनए परिणाम स्पष्ट नहीं आने पर दोबारा अलग प्रक्रिया से जांच करनी पड़ती है। थापा के मुताबिक, जांच पूरी होने में कितना समय लगेगा, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में कितने अतिरिक्त उपकरण उपलब्ध होते हैं और वे कितनी प्रभावी तरीके से काम करते हैं। नेपाल में डीएनए जांच के लिए सीमित संख्या में उपकरण होने के कारण विभिन्न देशों ने भी मदद की है। दक्षिण कोरिया द्वारा उपलब्ध कराए गए चार डीएनए उपकरण पुलिस की प्रयोगशाला में काम करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि, अन्य उपकरणों को अभी स्थापित किया जाना बाकी है।

मलेशियाई पीएम ने मुस्लिम समाज को चेताया, बोले- एआई को समझे बिना हम गुलाम बन जाएंगे

कुआलालंपुर/नई दिल्ली। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मुस्लिम विद्वानों और समुदायों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और उभरती तकनीकों को समझने और उनके साथ कदम मिलाकर चलने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि तकनीकी बदलावों से पीछे रहने पर मुस्लिम समाज बाहरी प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू व अन्य मीडिया के अनुसार, केरल के कोझिकोड में रविवार को एक पुरस्कार समारोह में अनवर इब्राहिम ने कहा, 'ज्ञान के बिना हम असफल हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझे बिना हम गुलाम बन जाएंगे।

उन्होंने करंतूर स्थित मरकजु सकफ़थी सुन्निय्या में शेख अबूबकर फाउंडेशन की ओर से दिए गए पहले 'एक्सीलेंस अवॉर्ड' को स्वीकार करने के बाद यह बात कही। गौरतलब है कि, अनवर इब्राहिम नई दिल्ली में ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद केरल पहुंचे थे। कोझिकोड में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एआई और आधुनिक तकनीक के दौर में मुस्लिम समाज के लिए शिक्षा, विशेषज्ञता और नैतिक मूल्यों के बीच संतुलन को महत्वपूर्ण बताया। अनवर इब्राहिम ने कहा कि धार्मिक विद्वानों को मौजूदा दौर की नई वास्तविकताओं और चुनौतियों को समझना होगा। इनमें आधुनिक तकनीक, नए वैज्ञानिक विकास, डिजिटल बदलाव और एआई प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता हासिल करने की जरूरत है, लेकिन तकनीकी विकास आस्था और नैतिक मूल्यों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि नई तकनीकों के साथ ऐसे विचार और मूल्य भी आ सकते हैं, जो धार्मिक आस्था और नैतिकता को कमजोर कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि मुस्लिम समाज तकनीक को केवल अपनाए ही नहीं, बल्कि उसे समझे और उसके विकास में अपनी भूमिका भी निभाए। अनवर ने कहा कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से जुड़े प्रमुख लोग एआई के संभावित जोखिमों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम विद्वानों और समुदायों के बीच इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने मुस्लिम समाज से एआई के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और तकनीकी बदलावों को समझने की अपील की।

नेतन्याहू पर पूर्व आईडीएफ प्रमुख का बड़ा आरोप- 2023 में हमास के हमले से पहले मिली थी चेतावनी

तेल अवीव। इज़राइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ डैन हलुत्ज़ ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर 7 अक्टूबर, 2023 के हमास हमले से पहले मिली संभावित चेतावनियों को छिपाने का गंभीर आरोप लगाया है। हलुत्ज़ ने इज़राइल की सुरक्षा में हुई चूक की राजनीतिक जिम्मेदारी सीधे नेतन्याहू पर डालते हुए कहा कि हमले से पहले कई संकेत मौजूद थे, लेकिन उन पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई। रूस की अंतरराष्ट्रीय समाचार टेलीविजन नेटवर्क रशिया टुडे (आरटी) के मुताबिक, हलुत्ज़ की यह टिप्पणी हारेट्ज़ की उस रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें दावा किया गया कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायद ने 7 अक्टूबर, 2023 के हमले से करीब दस दिन पहले नेतन्याहू को हमास द्वारा एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी के बारे में चेतावनी दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ने कथित तौर पर इस खतरे को कम करके आंका और सुरक्षा प्रमुखों को इसकी जानकारी नहीं दी। हालांकि, नेतन्याहू के कार्यालय ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे 'सरासर झूठ' बताया है। यूएई की ओर से इस कथित बातचीत की पुष्टि या खंडन नहीं किया गया है। इज़राइली रेडियो को दिए एक साक्षात्कार में हलुत्ज़ ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि नेतन्याहू और यूएई नेतृत्व के बीच ऐसी बातचीत हुई थी। उन्होंने दावा किया कि कई परिस्थितियां इस ओर इशारा करती हैं कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा अधिकारियों की तुलना में हमास की तैयारियों के बारे में अधिक जानकारी थी। उन्होंने कहा कि यदि बातचीत हुई ही नहीं होती, तो यूएई के नेता के लिए इसका खंडन करना आसान होता। उनके अनुसार, उपलब्ध संकेतों से यह सवाल उठता है कि नेतन्याहू को हमले की आशंका के बारे में कितना पता था और उन्होंने उस जानकारी को किस हद तक साझा किया।

हारेट्ज़ की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इज़राइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट को हमास के तत्कालीन नेता याह्या सिनवार की गतिविधियों को लेकर अलग चेतावनी मिली थी। कथित तौर पर सिनवार एक 'भूकंप' और 'भयानक ऑपरेशन' की तैयारी कर रहे थे और नेतन्याहू को इसकी जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, बाद की सुरक्षा समीक्षा में शिन बेट ने चेतावनी दी थी कि इज़राइल 'टकराव की स्थिति' की ओर बढ़ रहा है। एजेंसी ने गाज़ा और वेस्ट बैंक के आसपास संभावित बड़े हमले की स्थिति में कार्रवाई या सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सिफारिश भी की थी।

ब्रिक्स से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का आह्वान - एआई की निगरानी के लिए बने अंतरराष्ट्रीय तंत्र

नई दिल्ली/अंकारा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने ब्रिक्स देशों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन और निगरानी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र स्थापित करने का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि एआई की तकनीकी क्षमता इंसानों की उसे समझने, निगरानी करने और नियंत्रित करने की क्षमता से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू व स्थानीय मीडिया के अनुसार, नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए रामफोसा ने कहा कि एआई उत्पादकता और मानव प्रगति के नए दौर की शुरुआत कर सकता है। हालांकि, उन्होंने तेजी से शक्तिशाली होते एआई सिस्टम से जुड़े संभावित जोखिमों पर भी चिंता जताई।

रामफोसा ने कहा कि जिम्मेदारी और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर एआई असमानता, गरीबी और अविकास को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, यह चिकित्सा, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान और कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन उन्होंने उन्नत एआई सिस्टम से जुड़े कई संभावित खतरों का भी जिक्र किया। इनमें उन्नत साइबर ऑपरेशन, जैविक हथियारों के विकास में सहायता, स्वायत्त कार्रवाई, हेरफेर, बड़े पैमाने पर निगरानी और रोजगार पर असर शामिल हैं। कहा कि हमें न तो एआई से डरना चाहिए और न ही इसे लापरवाही से अपनाना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि मानव शासन एआई जितनी तेजी से आगे

बढ़े। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने एआई कंपनियों की स्वतंत्र बाहरी निगरानी की जरूरत पर जोर देते हुए एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई के विचारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एआई कंपनियों को औपचारिक बाहरी जांच, स्वतंत्र ऑडिट और सरकारी निगरानी के दायरे में होना चाहिए। रामफोसा ने विमानन, फार्मास्यूटिकल्स, परमाणु ऊर्जा और वित्तीय क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जिन उद्योगों का मानव सुरक्षा और कल्याण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, वहां नियामकीय निगरानी पहले से ही सामान्य व्यवस्था का हिस्सा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि ब्रिक्स देशों को एआई के स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय तंत्र बनाना चाहिए। उनके मुताबिक, इस व्यवस्था में मानव नियंत्रण के स्पष्ट सिद्धांत और गंभीर एआई घटनाओं की अनिवार्य रिपोर्टिंग शामिल होनी चाहिए। उन्होंने विकासशील देशों में संप्रभु एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए निवेश बढ़ाने और एआई की क्षमता बढ़ने के साथ सुरक्षा उपायों को भी मजबूत करने की जरूरत बताई। रामफोसा ने ब्रिक्स के लिए एआई इकोसिस्टम स्थापित करने के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रस्ताव का भी स्वागत किया और कहा कि दक्षिण अफ्रीका इस पहल का समर्थन करता है।

नेपाल चीन के बीच रसुवागढ़ी-केरूंग नाका बंद होने से कोरला-लिजी बॉर्डर पर बढ़ा व्यापारिक दबाव

काठमांडू,एजेंसी। नेपाल और चीन के बीच वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल होने वाले मुस्तांग जिले के कोरला-लिजी नाके पर पिछले दो हफ्तों से व्यापारिक गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। नेपाल-चीन के प्रमुख व्यापारिक नाके रसुवागढ़ी-केरुंग के 26 अगस्त से बाढ़ के कारण पूरी तरह बंद होने के बाद चीन से सामान का आयात अब कोरला नाके के जरिए किया जा रहा है। चीन ने फिलहाल तातोपानी नाका भी नहीं खोला है। ऐसे में नेपाल-चीन व्यापार के लिए कारोबारियों को कोरला-लिजी नाके का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।

रसुवा में बाढ़ के बाद चीन से नेपाल आने वाले सामान का दबाव बढ़ने से मुस्तांग कस्टम कार्यालय में रोजाना सैकड़ों मालवाहक वाहनों की जांच और क्लीयरेंस होने लगी है। कार्यालय के अनुसार, चीन से आने वाले सामान के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों का आयात भी इसी नाके से हो रहा है। मुस्तांग कस्टम प्रमुख विदुर चुडाल के अनुसार, फिलहाल रोजाना करीब 60 से 70 वाहनों का भंसार जांच-पास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर कंटेनरों में दशहरा को ध्यान में रखकर लाए गए सामान हैं। इसके अलावा औद्योगिक कच्चा माल और कुछ फल भी आयात किए जा रहे हैं। मुस्तांग कस्टम कार्यालय से अब तक कुल 482 कंटेनरों का भंसार जांच-पास हो चुका है। 26 अगस्त से पहले कोरोला नाके से जनवरी

से 10 अगस्त तक केवल 133 कंटेनरों की जांच-पास हुई थी, जबकि बाढ़ के बाद अकेले 349 कंटेनरों का क्लीयरेंस किया जा चुका है। रसुवागढ़ी नाका बंद होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहन भी मुस्तांग के रास्ते नेपाल पहुंच रहे हैं। कस्टम प्रमुख चुडाल के अनुसार, अब तक मुस्तांग भंसार से 757 इलेक्ट्रिक वाहनों का जांच-पास हो चुका है। बाढ़ से पहले तक केवल 163 ईवी का भंसार जांच-पास हुआ था। इसके बाद 594 इलेक्ट्रिक वाहनों का क्लीयरेंस किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि अभी भी करीब 300 से 400 इलेक्ट्रिक वाहन नाके पर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ का कस्टम क्लियरेंस बाकी है। तातोपानी नाका भी बंद रहने के कारण आने वाले दिनों में मुस्तांग के रास्ते ईवी आयात का दबाव बने रहने की संभावना है। फिलहाल, मुस्तांग नाके से व्यापारिक गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं और कस्टम कार्यालय इसी के प्रबंधन में जुटा हुआ है। रसुवागढ़ी नाका बंद होने के बाद मुस्तांग भंसार कार्यालय के राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चुडाल के अनुसार, शनिवार तक एक अरब 87 करोड़ नेपाली रुपये राजस्व जमा हो चुका था। रविवार को करीब 13 करोड़ और जमा होने के बाद कुल राजस्व लगभग 2 अरब पहुंच गया है। जबकि जनवरी से 26 अगस्त तक मुस्तांग कस्टम कार्यालय से केवल 53 करोड़ का राजस्व संग्रह हुआ था। बाढ़ के बाद कोरला को वैकल्पिक व्यापारिक नाके के रूप में इस्तेमाल किए जाने से कम समय में राजस्व संग्रह में बड़ी वृद्धि हुई है। रसुवागढ़ी नाका बाढ़ के कारण बंद होने के बाद विकल्प के तौर पर मुस्तांग नाके का इस्तेमाल बढ़ा है। इसके चलते दो महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और सरकार के सालाना राजस्व लक्ष्य का करीब एक-चौथाई हिस्सा पहले ही जमा हो चुका है।

हरितालिका तीज पर पशुपतिनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह 3 बजे से खोले गए चारों द्वार

काठमांडू,एजेंसी। हरितालिका तीज पर्व के अवसर पर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए महिला व्रती श्रद्धालुओं की सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। पशुपति क्षेत्र विकास कोष के अनुसार, हरितालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज सुबह 3 बजे से ही पशुपतिनाथ मंदिर के चारों द्वार खोल दिए गए। मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए चार अलग-अलग दर्शन मार्ग बनाए गए हैं।

कोष के सदस्य सचिव तीर्थ श्रेष्ठ ने बताया कि पहले मार्ग के तहत मित्रपार्क-उमाकुंड-दक्षिणामूर्ति-कैलाश बद्रीनरसिंह भवन होते हुए वासुकीनाथ के उत्तर दिशा वाले द्वार से श्रद्धालुओं को मंदिर के उत्तर दिशा के रैंप तक ले जाया जा रहा है। यहां से भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कराने के बाद श्रद्धालुओं को पश्चिमी द्वार से बाहर निकाला जा रहा है। दूसरे मार्ग में जयबागेश्वरी से बाईं ओर दथुटोल, पाचा गणेश, अन्नपूर्णा भंडार और महास्नानघर के सामने बने आकाशे पुल से भुवनेश्वरी और नासलचोक होते हुए शंकराचार्य मठ के सामने बने आकाशे पुल तक श्रद्धालुओं को ले जाया जा रहा है। वहां से पुलिस पहरा गण के छोटे द्वार और दो कतारों के जरिए पशुपति मंदिर के पश्चिमी हिस्से में बने लकड़ी के रैंप से दर्शन कराने के बाद पश्चिमी द्वार से बाहर निकाला जा रहा है। इसी तरह तीसरे मार्ग की व्यवस्था सिनामंगल और एयरपोर्ट की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है। उन्हें तिलगंगा पर्यटन काउंटर के पास स्थित द्वार, राम मंदिर और बागमती नदी के किनारे से आर्यघाट पुल होते हुए ब्रह्मनाल तक ले जाया जा रहा है।

इसके बाद पूर्वी द्वार पर बनाए गए रैंप से भगवान पशुपतिनाथ के पूर्वी स्वरूप के दर्शन कराकर उसी द्वार से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं, पिंगलास्थान की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पिंगलास्थान स्थित द्वार से प्रवेश की व्यवस्था की गई है। यहां से चार शिवालय और पंचदेवल वृद्धाश्रम के दक्षिण की ओर बने बड़े द्वार के सामने अस्थाई आकाशे पुल के जरिए छोटे द्वार से श्रद्धालुओं को चौंसट्ठी कोटीलिंगेश्वर होते हुए मंदिर के दक्षिणी स्वरूप के दर्शन कराए जा रहे हैं। इसके बाद उन्मत्त भैरव मंदिर के पश्चिमी हिस्से और मूल भट्ट निवास के सामने से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला जा रहा है। कोष के मुताबिक, सुबह के समय श्रद्धालु बिना ज्यादा परेशानी के कतार में लगकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर रहे हैं। करीब आधे घंटे तक कतार में रहने के बाद व्रती महिलाएं दर्शन करके वापस लौट पा रही हैं। सुबह के समय बारिश के बावजूद महिला श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और वे कतार में भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर रही हैं।

एक नजर

महाराष्ट्र मण्डल द्वारा आयोजित श्रीगणेश उत्सव पूजा में शामिल हुये मुख्यमंत्री

पटना,एजेंसी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी महाराष्ट्र मण्डल द्वारा सरपेंटाईन रोड, दारोगा प्रसाद राय पथ पटना में आयोजित श्रीगणेश उत्सव पूजा में शामिल हुये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधिवत पूजा-अर्चना कर भगवान श्रीगणेश से प्रदेशवासियों की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। महाराष्ट्र मण्डल के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री को पुष्प-गुच्छ, अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंटकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें पगड़ी भी पहनाया गया। मुख्यमंत्री ने श्रीगणेश उत्सव पूजा के आयोजन के लिये महाराष्ट्र मण्डल के सदस्यों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर शुभकामनायें देते हुये कहा कि भगवान श्रीगणेश सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करें तथा बिहार निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़े। इस अवसर पर सिविल विमानन विभाग के सचिव डॉ नीलेश रामचन्द्र देवरे, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक, मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर सहित महाराष्ट्र मण्डल के सदस्य, अन्य व्यक्ति एवं श्रद्धालु उपस्थित थे।

भारी बारिश के बीच खैराताबाद गणेश के दर्शन को उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, राज्यपाल ने भी की पूजा-अर्चना

हैदराबाद,एजेंसी। भारी बारिश के बावजूद हैदराबाद के खैराताबाद पंडाल में स्थापित 69 फीट ऊंचे पंचमुख संकटहर महा गणपति के दर्शन के लिए सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। विशाल प्रतिमा की एक झलक पाने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं और पंडाल परिसर दिनभर श्रद्धालुओं से भरा रहा। गणेश उत्सव समिति और स्थानीय पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने तथा श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारू रखने के लिए विशेष व्यवस्था की। खैराताबाद मेट्रो स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग पर भी पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई। इस बीच पद्मशाली संगम के सदस्यों ने खैराताबाद बड़ा गणेश को 75 फीट लंबा कंदुवा (पवित्र अंगवस्त्र), भव्य जंध्यम (जनेऊ) और गरिका माला (दूर्वा घास की माला) अर्पित की। संगम की परंपरा के तहत लगातार पांचवें वर्ष यह विशेष भेंट अर्पित की गई। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और उनकी पत्नी ने भी खैराताबाद गणेश पंडाल पहुंचकर प्रथम पूजा में हिस्सा लिया और पूजा-अर्चना की। खैराताबाद का गणेश पंडाल अपनी भव्य प्रतिमा और सजावट के लिए दक्षिण भारत में विशेष पहचान रखता है। गणेश चतुर्थी के दौरान हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

हिंदी केवल भाषा नहीं, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय अस्मिता की सशक्त अभिव्यक्ति है: महापौर

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में हिंदी दिवस के अवसर पर सोमवार को हिंदी दिवस एवं राजभाषा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर प्रवेश वाही और नेता सदन जय भगवान यादव उपस्थित रहें। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि हिंदी देश की विविधताओं को जोड़ने वाली सशक्त कड़ी है। भारत की पहचान उसकी भाषाई एवं सांस्कृतिक समृद्धि से है और हिंदी इस बहुरंगी विरासत को एक व्यापक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी का सम्मान केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक कार्यों और व्यवहार का हिस्सा बनाना आवश्यक है। निगम के कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग से प्रशासन और आम नागरिकों के बीच संवाद को और अधिक सहज एवं प्रभावी बनाया जा सकता है।

महापौर ने कहा कि हिंदी का विकास तभी सार्थक है, जब देश की सभी भारतीय भाषाओं का समान रूप से सम्मान और विकास हो। भारत की भाषाई विविधता हमारी शक्ति है और प्रत्येक भाषा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की वाहक है। उन्होंने निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की कि वे कार्यालयीन कार्यों, पत्राचार एवं जनसंचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दें तथा राजभाषा के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भागीदारी निभाएं। नेता सदन जय भगवान यादव ने कहा कि हिंदी हमारी भावनाओं, संस्कृति और सामाजिक

जुड़ाव की भाषा है। राजभाषा का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब हिंदी का प्रयोग कार्यालयीन कार्यों के साथ-साथ जनसेवा के प्रत्येक स्तर पर बढ़े। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त डॉ सतेन्द्र सिंह दुर्सावत ने केंद्रीय गृह मंत्री के संबोधन को पढ़कर सुनाया, जिसमें हिंदी भाषा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भारत की भाषाई समृद्धता एवं बहुलता को देश की शक्ति बताया गया। संबोधन में कहा गया कि भारत की भाषाई बहुलता देश को और अधिक सशक्त एवं समृद्ध बनाती है तथा हिंदी का विकास तभी सार्थक है, जब सभी भारतीय भाषाएं समान रूप से आगे बढ़ें। समारोह के दौरान हिंदी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले नंदिनी श्रीवास्तव, सूरज त्रिपाठी, रागिनी झा, योगेश तथा बाल कवयित्री सानवी जैन सहित कवियों एवं साहित्यिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी भाषा की गरिमा, भारतीय संस्कृति, सामाजिक सरोकारों एवं राष्ट्रभावना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उप महापौर एवं हिंदी समिति की अध्यक्ष, डॉ. मोनिका पंत, हिंदी समिति की उपाध्यक्ष मनीषा सिंह ,पार्षद गुलाब सिंह, राम प्रसाद गहलोत, मनीषा, ऋतु गोयल एवं नीता बिष्ट सहित निगम के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

बेरोजगार पत्नी और चार साल के बच्चे के लिए 7,500 रुपये गुजारा भत्ता ज्यादा नहीं: हिमाचल उच्च न्यायालय

शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता से जुड़े एक मामले में कहा है कि बेरोजगार पत्नी और चार साल के बच्चे के लिए 7,500 रुपये प्रति माह की कुल राशि किसी भी तरह से अधिक नहीं मानी जा सकती। अदालत ने कहा कि मौजूदा समय में इस राशि से बच्चे की पढ़ाई, उसकी बुनियादी जरूरतों और जीवनयापन का खर्च उठाना आसान नहीं है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने पति की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। मामले में मंडी के प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे के पक्ष में कुल 7,500 रुपये की मासिक रखरखाव राशि मंजूर की थी। इसमें चार हज़ार रुपये पत्नी और 3,500 रुपये बच्चे के लिए तय किए गए थे। पारिवारिक न्यायालय ने इसके अलावा मुकदमे के खर्च के लिए आठ हजार रुपये देने का भी आदेश दिया था। इसी आदेश को पति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पत्नी की ओर से आरोप लगाया गया था कि बच्चे के जन्म के समय उसके ससुराल पक्ष से कोई भी उसे देखने नहीं आया और बच्चे के जन्म से जुड़े सभी खर्च उसके माता-पिता ने उठाए। बाद में पति के परिवार ने उसे वापस ससुराल ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह मानसिक तनाव के कारण अपने पिता के घर रहने को मजबूर हुई।

पत्नी के पास वर्तमान में आय का कोई साधन नहीं है और वह अपने माता-पिता पर निर्भर है। हाईकोर्ट ने यह भी ध्यान में रखा कि बच्चा अब चार साल का हो चुका है और स्कूल जाने लगा है। इससे उसकी पढ़ाई और अन्य जरूरतों का खर्च बढ़ना स्वाभाविक है। अदालत ने माना कि ऐसी स्थिति में पत्नी और बच्चे के लिए तय 7,500 रुपये की मासिक राशि अधिक नहीं है। अदालत के अनुसार पत्नी के पास अपनी आय का कोई साधन नहीं होने और बच्चे की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए यह राशि उनके जीवनयापन के लिए जरूरी है। खंडपीठ ने इन परिस्थितियों में पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।

हिंदी दिवस पर जीडीसी महानपुर में साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

महानपुर। राजकीय डिग्री कॉलेज महानपुर में सोमवार को हिंदी दिवस उत्साह और साहित्यिक रंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व, उसके ऐतिहासिक विकास तथा समृद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत को उजागर करना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉ. संगीता सूदन ने दीप प्रज्वलित कर की। विद्यार्थियों ने रंगोली, कविता पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से हिंदी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। पांचवें सेमेस्टर की छात्राओं ने कबीर के दोहों की सुंदर प्रस्तुति दी जबकि तीसरे सेमेस्टर की छात्रा साक्षी ने हिंदी दिवस के महत्व पर विचार रखे। हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर एवं कार्यक्रम की आयोजक डॉ. सपना देवी ने हिंदी भाषा के इतिहास और विकास पर जानकारी साझा की। उन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों और प्रमुख साहित्यकारों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों से हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने हिंदी को समर्पित अपनी स्वरचित कविता भी प्रस्तुत की। प्राचार्य डॉ. संगीता सूदन ने विद्यार्थियों और आयोजन टीम को बधाई देते हुए हिंदी के प्रति गौरव की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। अंत में तीसरे सेमेस्टर की छात्रा सोनिका ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सहारनपुर से मुख्यमंत्री योगी ने शुरू किया था धारा-24 महा-अभियान, डिजिटल तकनीक से होगा सीमांकन

लखनऊ,एजेंसी। उत्तर प्रदेश में जमीन की पैमाइश और सीमांकन की प्रक्रिया अब तकनीक की नई रफ्तार पकड़ रही है। योगी सरकार राजस्व विभाग के कामकाज को आधुनिक बनाने के लिए जीएनएसएस रोवर तकनीक को बड़े स्तर पर जमीन पर उतार रही है। प्रदेश में उपलब्ध 504 जीएनएसएस रोवर में से 350 रोवर तहसीलों तक पहुंचाए जा चुके हैं और इनसे काम भी शुरू हो गया है। वहीं 143 रोवर 10 यूएलबी की नक्शा परियोजनाओं में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हरदोई के केटीएस (चकबंदी प्रशिक्षण केंद्र) में दो रोवर लगाए गए हैं, जबकि लेखपाल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए खरीदे गए 9 रोवर से सभी प्रशिक्षण पूरे हो चुके हैं। यह बदलाव जमीन की पैमाइश को पारंपरिक तरीकों से निकालकर अधिक तेज, सटीक और डिजिटल व्यवस्था की ओर ले जा रहा है।

राजस्व परिषद आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने बताया कि जीएनएसएस रोवर की तैनाती केवल तहसीलों तक सीमित नहीं है। 350 रोवर सीधे तहसीलों में पहुंचने के बाद फील्ड सर्वेक्षण में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके साथ 143 रोवर 10 यूएलबी (शहरी स्थानीय निकाय) की नक्शा परियोजनाओं के लिए लगाए गए हैं। हरदोई के केटीएस को भी दो रोवर उपलब्ध कराए गए हैं। दूसरी ओर, लेखपाल प्रशिक्षण संस्थानों के लिए खरीदे गए 9 रोवर का इस्तेमाल प्रशिक्षण में किया गया और सभी प्रशिक्षण पूरे हो चुके हैं। यानी राजस्व विभाग में तकनीक के इस्तेमाल के साथ कर्मचारियों को इसके संचालन के लिए तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। कंचन वर्मा ने कहा कि भूमि की सीमाओं और पैमाइश से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए धारा-24 का विशेष महाअभियान 1 जुलाई से 15 अगस्त तक चलाया

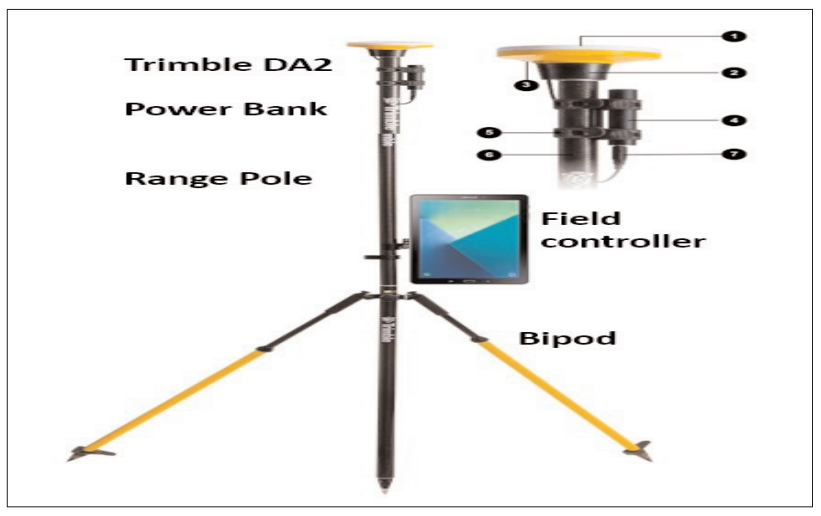

गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई को सहारनपुर से इस अभियान की शुरुआत की थी। अभियान को प्रभावी और एक समान तरीके से संचालित करने के लिए राजस्व विभाग ने एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) भी जारी की। अब इसी व्यवस्था को आधुनिक सर्वे तकनीक का सहारा मिलने से जमीन से जुड़े कामों में तकनीकी क्षमता बढ़ी है। जीएनएसएस रोवर आधुनिक सर्वेक्षण उपकरण है, जो विभिन्न उपग्रह प्रणालियों से मिलने वाले सिग्नल के आधार पर जमीन पर किसी बिंदु की सटीक स्थिति निर्धारित करता है। उत्तर प्रदेश के नेटवर्क से जुड़ने पर यह लगभग 1 से 5 सेंटीमीटर तक सटीक जानकारी दे सकता है। सर्वेक्षक खेत या भूमि की सीमा के प्रमुख बिंदुओं के डिजिटल निर्देशांक (कोऑर्डिनेट्स) दर्ज करते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर की मदद से दूरी और क्षेत्रफल की गणना की जाती है व डिजिटल नक्शा तैयार किया जाता है। जमीन की पैमाइश के पारंपरिक तरीकों में जंजीर और फीते के इस्तेमाल की तुलना में रोवर तकनीक सर्वेक्षण को अधिक वैज्ञानिक और डिजिटल बना रही है। फील्ड में जुटाए गए डिजिटल निर्देशांकों को जीआईएस और भूमि रिकॉर्ड प्रणालियों से जोड़ा जा सकता है। इससे तैयार डेटा को सुरक्षित रखना, उसकी गुणवत्ता जांचना और जरूरत के समय उसका इस्तेमाल करना आसान बन रहा है। रोवर से तैयार डिजिटल डेटा भूमि रिकॉर्ड और नक्शा प्रणालियों को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद कर रहा है। रिकॉर्ड की गुणवत्ता जांचने और डेटा की ट्रेसबिलिटी बनाए रखने में भी सुविधा है। भूमि पार्सल सर्वेक्षण, कडास्ट्रल मैपिंग, नक्शा परियोजनाओं और जीआईएस आधारित मैपिंग में इसका इस्तेमाल राजस्व प्रशासन को आधुनिक बनाने में सहायता प्रदान कर रहा है।

भारत-जापान के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को शिक्षा और तकनीक दे रहे नया विस्तार: विष्णुदेव साय

रायपुर,एजेंसी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज सोमवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जापान की एहिमे यूनिवर्सिटी से आए 17 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। भारत-जापान इंटर एक्सचेंज कार्यक्रम के अंतर्गत तीन दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर छत्तीसगढ़ पहुंचे विद्यार्थियों से मुख्यमंत्री साय ने आत्मीय संवाद किया। इस दौरान भारत और जापान के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों, बौद्ध विरासत, शिक्षा, अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप तथा दोनों देशों के युवाओं के बीच बढ़ते संवाद सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापानी छात्र-छात्राओं का छत्तीसगढ़ की धरती पर आत्मीय स्वागत करते हुए कहा कि भारत और जापान की मित्रता की जड़ें दोनों देशों की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में गहराई से जुड़ी हुई हैं। समय के साथ यह संबंध संस्कृति और आध्यात्मिकता से आगे बढ़कर शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, नवाचार और आर्थिक सहयोग के अनेक क्षेत्रों तक विस्तृत हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और जापान आज परंपरा और आधुनिकता के सुंदर समन्वय के साथ विश्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और सम्मान की मजबूत नींव है। युवाओं तथा विद्यार्थियों के बीच इस प्रकार के

शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान से यह संबंध आने वाली पीढ़ियों में और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने जापानी विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध पुरातात्विक विरासत की जानकारी देते हुए सिरपुर, मैनपाट और भोंगापाल जैसे महत्वपूर्ण स्थलों का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महानदी के तट पर स्थित सिरपुर छत्तीसगढ़ की प्राचीन सभ्यता, कला, स्थापत्य और बौद्ध विरासत का अद्भुत केंद्र है। यहां प्राप्त पुरातात्विक अवशेष प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय की कहानी बताते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपनी जापान यात्रा से जुड़े अनुभव भी विद्यार्थियों के साथ साझा किए। उन्होंने जापान की अनुशासित कार्यसंस्कृति, तकनीकी प्रगति और अपनी परंपराओं के प्रति सम्मान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान ने आधुनिक विज्ञान और तकनीक में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपनी सांस्कृतिक पहचान को जिस प्रकार सहेजकर रखा है, वह प्रेरणादायी है। जापानी छात्र प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के साथ अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के अनुभव भी साझा किए। विद्यार्थियों ने बताया कि रायपुर में उन्हें अत्यंत आत्मीय अनुभव हुआ। यहां की संस्कृति, परंपराओं और लोगों के सहज एवं आत्मीय व्यवहार ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया। विद्यार्थियों ने भारतीय खान-पान की भी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान उन्हें गणेश उत्सव की परंपराओं और उसके सांस्कृतिक महत्व को करीब से जानने का अवसर मिला। जापानी छात्राओं ने उत्साहपूर्वक बताया कि उन्होंने मेहंदी लगवाई और भारतीय परिधानों की खरीदारी भी की। विद्यार्थियों ने कहा कि इस यात्रा ने उन्हें भारत को पुस्तकों और कक्षाओं से आगे बढ़कर यहां के समाज, संस्कृति और जीवनशैली के माध्यम से समझने का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री साय ने विद्यार्थियों के अनुभव सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि छत्तीसगढ़ अपनी सहजता, आत्मीयता और अतिथि सत्कार की परंपरा के लिए जाना जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे यहां से छत्तीसगढ़ की सुखद स्मृतियां लेकर जाएं और भविष्य में पुन: प्रदेश आएं। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान जापानी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने एनआईटी रायपुर के विभिन्न रिसर्च सेंटरों और इन्क्यूबेशन सेंटर का भी भ्रमण किया। विद्यार्थियों ने वहां संचालित स्टार्टअप की गतिविधियों, अनुसंधान परियोजनाओं और विकसित की जा रही नई तकनीकों की जानकारी ली। विशेष रूप से ऐसे स्टार्टअप ने जापानी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया, जो तकनीक के माध्यम से आम लोगों की दैनिक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान विकसित कर रहे हैं।

मणिपुर में विभिन्न उग्रवादी संगठनों के कैडर और वसूलीकर्ता गिरफ्तार, हेरोइन व नशीली कैप्सूल बरामद

इंफाल,एजेंसी। मणिपुर में सुरक्षा बलों और पुलिस ने बीते 24 घंटे में चलाए गए अलग-अलग अभियानों में विभिन्न प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों से जुड़े कई सक्रिय कैडरों और कथित वसूलीकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस दौरान मादक पदार्थ भी बरामद किए गए।

असम राइफल्स से मिली सूचना के आधार पर सीडीओ-इंफाल पश्चिम की टीम ने मोइदांगपोक इलाके में अभियान चलाकर केसीपी (पीडब्ल्यूजी) के सक्रिय कैडर 26 वर्षीय थांगजाम सनातोम्बा सिंह उर्फ थेम्बुंग को गिरफ्तार किया। वह मोइदांगपोक माखा लीकाई का रहने वाला है। एक अन्य अभियान में सीडीओ-इंफाल पश्चिम ने तकीयेल खोंगबल लैराक अचौबा इलाके में तलाशी अभियान चलाकर केसीपी (अपुनबा) के सक्रिय सदस्य 26 वर्षीय संजेनबाम अल्बर्ट मीतेई उर्फ लुखोई को उसके आवास से गिरफ्तार किया। उस पर वसूली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पटसोई यूनिक-खोंग बाजार इलाके में चलाए गए अभियान में पीआरई-पीएके (पीआरओ) के सदस्य 48 वर्षीय खोंगबंतबाम इनाओ सिंह उर्फ इबोयाइमा को

गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 18,500 नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। इधर, लिलोंग थाना और सीडीओ-थौबल की संयुक्त टीम ने लिलोंग उसोइपोकपी से बीबी लेइहान (66) और मोहम्मद फारूक (40) को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 182 एसपी कैप्सूल तथा कुल 133 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इसमें 12 ग्राम हेरोइन एक साबुनदानी में और 121 ग्राम हेरोइन 91 प्लास्टिक शीशियों में रखी हुई थी। एक अन्य संयुक्त अभियान में सीडीओ-इंफाल पूर्व और 31 असम राइफल्स ने फाकनुंग, इंफाल पूर्व से केसीपी (अपुनबा) के दो कथित वसूलीकर्ताओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सेक्टा मायाई लीकाई निवासी फिजाम चिंगतम मीतेई (22) और हिजाम नानाओ मीतेई उर्फ अकानाओ (25) के रूप में हुई है। संबंधित मामलों में पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)